₹ 10

www.kewalsachtimes.com

दिसम्बर 2023

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

RNI NO.-BIHBIL/2011/49252, DAVP NO.-131729, POSTAL REG. NO.:-PT.-78

उपराष्ट्रपति का अपमान !

जन-जन की आवाज है केवल सच

केवल सच
हिन्दी मासिक पत्रिका

Kewalachlive.in
वेब पोर्टल न्यूज
24 घंटे आपके साथ

Kewalsach news
खबर वहीं, जो केवल सच हो

केवल सच TIMES

आत्म-निर्भर बनने वाले युवाओं को सपोर्ट करें

आपका छोटा सहयोग, हमें मजबूती प्रदान करेगा

BHIM | UPI
G Pay पे paytm

www.kewalsach.com
www.kewalsachlive.in

-: सम्पर्क करें :-

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या-28/14,
कंकड़बाग, पटना (बिहार)-800020, मो०:-9431073769, 9308815605

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ

मेधा पाटकर
01 दिसम्बर 1954

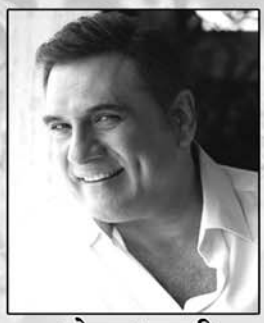

बोमन इरानी
02 दिसम्बर 1959

जावेद जाफरी
04 दिसम्बर 1963

प्रकाश सिंह बादल
08 दिसम्बर 1927

सोनिया गांधी
09 दिसम्बर 1946

शत्रुध्न सिन्हा
09 दिसम्बर 1945

स्व० प्रणव मुखर्जी
11 दिसम्बर 1935

विश्वनाथन आनंद
11 दिसम्बर 1969

शरद पवार
12 दिसम्बर 1940

रजनीकान्त
12 दिसम्बर 1950

युवराज सिंह
12 दिसम्बर 1981

जॉन अब्राहम
17 दिसम्बर 1972

प्रतिभा देवी पाटिल
19 दिसम्बर 1934

गोविन्दा
21 दिसम्बर 1963

अनिल कपूर
24 दिसम्बर 1959

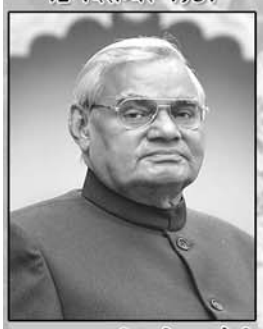

स्व० अटल बिहारी बाजपेयी
25 दिसम्बर 1924

स्व० राजू श्रीवास्तव
25 दिसम्बर 1963

सलमान खान
27 दिसम्बर 1965

स्व० अरूण जेटली
28 दिसम्बर 1952

रतन टाना
28 दिसम्बर 1937

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar) Mob.-09431073769,
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Vaishnavi Enclave, Second Floor, Flat No. 2B, Near-firing range, Bariatu Road, Ranchi- 834001
E-mail :- editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha
A-68, 1st Floor, Nageshwar talla, Shastri Nagar, New Delhi-110052
Mob.- 09868700991, 09955077308
kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube,
131 Chitranjan Avenue, Near- md. Ali Park, Kolkata- 700073 (West Bengal)
Mob.- 09433567880, 09339740757

ADVERTISEMENT RATES PER ISSUE

COLOUR

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
Cover Page	3,00,000/-	N/A
Back Page	1,00,000/-	65,000/-
Back Inside	90,000/-	50,000/-
Back Inner	80,000/-	50,000/-
Middle	1,40,000/-	N/A
Front Inside	90,000/-	50,000/-
Front Inner	80,000/-	50,000/-

B & W

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
Inner Page	60,000/-	40,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट **www.kewalsachtimes.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

भारत में बज रहा है मोदी का डंका

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com

मोदी - मोदी - मोदी - मोदी के नारा जितना BJP के कार्यकर्त्ता लगाते हैं उससे कहीं ज्यादा विरोध करने के चक्कर में विपक्षी लगाते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेन्द्र दामोदर दास मोदी ने देश के सभी राज्यों में चुनाव प्रचार एवं भारत सरकार की योजनाओं को लेकर जनमानस के बीच सदैव सक्रिय रहने का कोई अवसर नहीं छोड़ते और सनातन धर्म का प्रचार की वजह से उनकी लोकप्रियता का डंका न सिर्फ India बल्कि विदेशों में भी बज रहा है। 2019 में 303 सीट जीतने के बाद World में भी मोदी की लोकप्रियता का डंका बज रहा है जिसकी वजह से 2024 में भी BJP की सरकार बनने के आसार दिख रहे हैं क्योंकि मोदी को PM के पद से हटाने के लिए INDIA गठबंधन पर गठबंधन के लोगों का ही विश्वास नहीं रह गया है। उत्तर प्रदेश में काशी से PM मोदी बनकर 02 बार MP बन चुके हैं और तीसरी बार भी जीतेंगे क्योंकि अयोध्या, काशी और मथुरा के विवाद को मुद्दा बनाकर BJP 02 सीट से बढ़कर 303 पहुंच चुकी है जिसमें काशी कोरिडोर को इतना साफ कर दिया है कि आधी समस्या समाप्त हो गया और अयोध्या का फैसला सुप्रीम कोर्ट दे चुका है और मथुरा का राजनीतिक खेल भी शुरू हो चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश के भीतर मजबूत माहौल BJP का बन जायेगा और महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा INDIA गठबंधन सनातन धर्म के आगे गौण हो जायेगा। पाकिस्तान और चीन को PM मोदी ने धर्म-संकट में डाल दिया है और देश के हर राज्यों में मोदी - मोदी - मोदी का खेल जोरों पर चल रहा है और गठबंधन हैरत में है।

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में BJP की प्रचंड जीत के बाद पूरे देश में PM मोदी की लोकप्रियता की डंका बजने लगी है और 2024 में सरकार बनने के स्पष्ट आधार दिखने लगा है। अटल और आडवाणी एवं जोशी की BJP 2014 के बाद अब मोदी एवं शाह की बन चुकी है और कब किसको आगे बढ़ाना है पार्टी के भीतर भी तब पता चलता है जब सारा खेल पूर्ण हो जाता है। 2023 के अंत में हुए विधानसभा चुनाव में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत से उत्साहित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे ''**मोदी की गारंटी**'' पर ''**जनता के विश्वास की गारंटी**'' का परिणाम बताया है। गुजरात के बतौर मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात में विकास का एक ऐसा मॉडल तैयार किया, जिससे देश के भीतर भाजपा की साख मजबूत हुई और हिन्दूवादी विचार के कारण गोधरा कांड ने मोदी की लोकप्रियता सनातन प्रेमियों के बीच इतना सुदृढ़ बना दिया कि 2014 के लोकसभा चुनाव में पहली बार भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का आंकड़ा अकेले दम पर पार कर ली और NDA को भी आपार सफलता मिली। आते ही कई योजना एवं कानून बनाने पर जोर दिया और बनाया भी, जिसमें धारा-370 एवं CAA ने भारतवंशियों को यह एहसास कराया कि मोदी का डंका बजता रहेगा। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को प्राण-प्रतिष्ठा होने के बाद विश्व के पटल पर भी मोदी का डंका बजेगा। पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य चर्चित देश भी मोदी का लोहा मानते हैं। 2014 एवं 2019 में मोदी PM बनकर भारत में कई ऐसी योजना को लायी जिससे आम आदमी लाभान्वित हुआ। जिसमें जन धन योजना- 28 अगस्त, 2014, कौशल भारत मिशन- 28 अगस्त, 2014, मेक इन इंडिया- 28 सितंबर, 2014, मिशन स्वच्छ भारत- 2 अक्टूबर, 2014, सांसद आदर्श ग्राम योजना- 11 अक्टूबर 2014, श्रमेव जयते योजना- 16 अक्टूबर 2014, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ- 22 जनवरी, 2015, हृदय योजना- 21 जनवरी 2015, पीएम मुद्रा योजना- 8 अप्रैल, 2015, उजाला योजना- 1 मई, 2015, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना- 8 मई, 2015, कुल पेंशन योजना- 9 मई 2015, जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री- 9 मई, 2015, स्मार्ट सिटी पहल- 9 मई, 2015, अमृत रणनीति- 25 जून, 2015, डिजिटल इंडिया मिशन- 2 जुलाई, 2015, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना- 5 नवंबर, 2015, सॉवरेन गोल्ड ब्रांड की योजना- 5 नवंबर, 2015, उदय- 20 नवंबर, 2015, स्टार्ट-अप इंडिया- 16 जनवरी, 2016, सेतु भारतम योजना- 4 मार्च 2016, खड़े हो जाओ, भारत- 5 अप्रैल, 2016, ग्रामोदय से भारत उदय- 14-24 अप्रैल, 2016, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना- 1 मई 2016, नमामि गंगे योजना- 7 जुलाई 2016 के बाद भी कई योजना एवं कानून को लाया, जिसकी वजह से मोदी की साख मजबूत हुई है। आजाद भारत में संसद भवन का भी उद्घाटन करने के बाद विपक्षी एकता मोदी को पनौती तक की संज्ञा से नवाज रहे हैं लेकिन मोदी-शाह की जोड़ी ने ''**मोदी की गारंटी**'' की बात कहकर राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को बेदखल कर दिया और प्रचंड बहुमत में BJP ने सरकार बना ली। उज्जवला योजना एवं आयुष्मान भारत जैसे महत्वकांक्षी योजनाओं से देश की उन जनता को बहुत राहत मिली है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। मुद्रा लोन की वजह से छोटे-छोटे रोजगार भी बढ़ा है और कोरोना के समय उस लोन में कई प्रकार की सुविधा देकर लोगों का विश्वास जीता है। पक्ष एवं विपक्ष दोनों दल के नेता जो मोदी का विरोध करते हैं वह भी भारत की विदेश नीति का लोहा मानते हैं और न सिर्फ भारत बल्कि अन्य देश भी मोदी की कूटनीति को स्वीकार करते हैं। पाकिस्तान एवं चीन के भीतर जब मोदी-मोदी की चर्चा होने लगी है। कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दल को मोदी खुद एजेंडा देते हैं और उसपर BJP कार्य करती है जिसकी वजह से विपक्ष खुद ही बयान देकर फंस जाता है और देश के भीतर उसकी किरकिरी होने लगती है। मोदी ने भाजपा पर अपनी कमान इतनी मजबूत कर ली है कि बगैर उनकी इच्छा के एक टिकट भी कोई नहीं ले सकता और साधारण से साधारण कार्यकर्त्ता को भी मुख्यमंत्री का ताज मिल सकता है की बात भी 2023 के अंत में देखने को मिला, जिसकी वजह से भी पार्टी के कार्यकर्त्ता अब और मोदी-मोदी करने लगे हैं। किसान एवं ड्राईवर वाला कानून को भले ही मोदी ने समय की मांग को ध्यान में रखकर चुप हो जायें लेकिन मोदी एवं शाह के कार्य करने की पद्धति से विपक्ष एवं अन्य संगठन भी परिचित हो चुके हैं। काशी कोरिडोर एवं अयोध्या का कार्य को देखते हुए हिन्दूओं के बीच यह साफ हो गया है कि मथुरा में भगवान श्रीकृष्ण भी विराजमान हो जायेंगे। एक तरफ देश में मोदी-मोदी हो रहा है और यह गाना गाया जा रहा है कि जो राम को लायें हैं, हम उनको लायेंगे तो दूसरी तरफ विपक्ष यह कहता है कि बीमार होने पर मंदिर जाने से ईलाज नहीं होगा बल्कि हॉस्पीटल जाने से जबकि हॉस्पीटल के डॉक्टर भी यही कहते हैं मैंने अपना प्रयास कर दिया है बाकी भगवान के हाथ में है, यह बात डॉक्टर समझते हैं लेकिन विपक्षी दल के नेता को सत्ता के लालच में यह नहीं दिखता। मोदी-मोदी का नारा जब देश के बाहर लग रहा है तब भी विपक्षी को इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि मोदी मैजिक है और इसको खरीदा नहीं जा सकता और इसकी बानगी जम्मू-कश्मीर में तिरंगा और देश के प्रति आस्था को देखने को मिल रहा है, जहां खून की नदियां बहती थी। धारा-370 हटने के बाद घाटी में भी मोदी का डंका बज रहा है।

KEWAL SACH TIMES
A National Magazine
वर्षः- 13, अंकः- 150 माहः- दिसम्बर 2023 रू. 10/-

Editor
Brajesh Mishra 9431073769
6206889040
8340360961
editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach@gmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

Principal Editor
Arun Kumar Banka 7782053204
Surjit Tiwary 9431222619
Nilendu Kumar Jha 9431810505

General Manager (H.R)
Triloki Nath Prasad 9308815605

General Manager (Advertisement)
Manish Kamaliya 6202340243
Poonam Jaiswal 9430000482

Joint Editor/Lay-out Editor
Amit Kumar 9905244479
amit.kewalsach@gmail.com

Legal Editor
Amitabh Ranjan Mishra 8873004350
S. N. Giri 9308454485

Asst. Editor
Mithilesh Kumar 9934021022
Sashi Ranjan Singh 9431253179
Rajeev Kumar Shukla 7488290565
Kamod Kumar Kanchan 8971844318

Sub. Editor
Arbind Mishra 6204617413
Prasun Pusakar 9430826922
Brajesh Sahay 7488696914

Bureau Chief
Sanket kumar Jha 7762089203
Sagar Kumar 9155378519

Bureau
Sridhar Pandey 9852168763
Sonu Kumar 8002647553

Photographer
Mukesh Kumar 9304377779

प्रदेश प्रभारी

दिल्ली हेड
संजय कुमार सिन्हा 9868700991

झारखण्ड हेड
ब्रजेश मिश्र (2) 7979769647
7654122344

पश्चिम बंगाल हेड
अजीत दुबे 9433567880
9339740757

मध्यप्रदेश हेड
अभिषेक पाठक 8109932505
8269322711

छत्तीसगढ़ हेड
आवश्यकता है

उत्तर प्रदेश हेड
निर्भय कुमार मिश्रा 9452127278

उत्तराखण्ड हेड
आवश्यकता है

महाराष्ट्र हेड
आवश्यकता है

गुजरात हेड
आवश्यकता है

आंध्र प्रदेश हेड
आवश्यकता है

राजस्थान हेड
आवश्यकता है

पंजाब हेड
आवश्यकता है

हरियाणा हेड
आवश्यकता है

राजस्थान हेड
आवश्यकता है

उड़ीसा हेड
आवश्यकता है

आसाम हेड
आवश्यकता है

हिमाचल हेड
आवश्यकता है

दिल्ली कार्यालय
केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
A-68, 1st Floor,
नागेश्वर तल्ला, शास्त्रीनगर, न्यू
दिल्ली-110052
मो०- 9868700991, 9431073769

पश्चिम बंगाल कार्यालय
केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल- 700073
मो०- 9433567880, 9339740757

झारखण्ड कार्यालय
केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
वैष्णवी इंक्लेव, द्वितीय तल,
फ्लैट नं- 2बी
नियर- फायरिंग रेंज
बरियातु रोड, राँची- 834001
मो०- 9308815605

मध्यप्रदेश कार्यालय
केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
द्वारा- अभिषेक कुमार पाठक
हाउस नं.-28, हरसिद्धि कैम्पस
खुशीपुर, चांबड़
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462010
मो०- 8109932505,

विशेष प्रतिनिधी
भारती मिश्र 8521308428
बेंकटेश कुमार 8210023343
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

प्रकाशित आलेख पर आप अपना सुझाव एवं प्रतिक्रिया अवश्य दें।

केवल सच टाइम्स

द्विभाषीय मासिक पत्रिका

हमारा पता है

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14,
मकान संख्या:- 14/28, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
सम्पर्क करें:- 9431073769, 8340360961

हमारा ई-मेल

editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

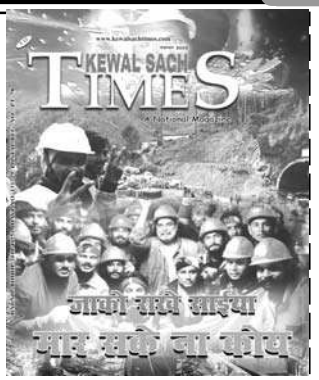

नवम्बर 2023

सुरंग हादसे

मिश्रा जी,

मैं आपकी पत्रिका का नियमित पाठक हूं और नवंबर 2023 अंक में **''उत्तराखंड की सिलक्यास सुरंग हादसे की टाइमलाइन''** सुरंग में फंसे मजूदरों की गतिविधियों तिथिवार जानकारी वास्तव में सूचनाप्रद है। जिस प्रकार मजदूरो को सुरक्षित निकालने का प्रयास किया गया और सकुशल वापस कराया गया वह फर्क करने वाला है। मोदी की सरकार ने यह साबित किया है कि मजदूरों की रक्षा के लिए केन्द्र एवं उत्तराखंड सरकार ने पूरी शक्ति के साथ मजूदरों की सकुशल वापसी के लिए पूरी टीम के साथ लगकर बचाया गया। खबर की जानकारी सटीक है।

● **रौशन तिवारी, रेलवे क्वार्टर, भोपाल, एमपी**

हिन्दुत्व एजेंडा

संपादक महोदय,

केवल सच टाइम्स पत्रिका में राजनीतिक खबरों को पूरी प्राथमिकता दिया जाता है तथा सनातन की खबरों को निश्चित तौर पर प्रकाशित करता है। नवंबर 2023 अंक में प्रकाशित **''राम के बाद अब श्रीकृष्ण भाजपा के हिन्दुत्व एजेंडे को देंगे धार''** खबर में भारत के वोटर की मानसिकता को ध्यान में रखकर मोदी का कारवां बढ़ रहा है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने के बाद राजनीतिक लाभ के लिए मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि का खेल भी शुरू हो चुका है। मोदी के नाम पर भारत देश में हिन्दुत्व का परचम फहराया है।

● **कुणाल सहाय, श्याम बाजार, कोलकात्ता**

विश्वकप विजेता

संपादक महोदय,

नवम्बर 2023 में विश्वकप का फाइनल की खबर में अमित कुमार ने पूरे खेल को विस्तार पूर्वक **''ऑस्टेलिया छठी बार विश्वकप विजेता''** लिखा है। विश्वकप का सभी 10 मैच जीतकर फाइनल मैच में हार का सामना करना पड़ा, जिससे विपक्ष के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पनौती तक कहा, क्योंकि भारत के प्रधान भी इस मैच को देखने को गये थे। मैच हारने के बाद निराश खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने का काम भारत के प्रधानमंत्री ने किया तथा उनको 10 मैच लगातार जितने की बधाई भी दी। ऑस्ट्रेलिया की जीत को लोग अन्य नजरिये से भी देखते हैं। पूरे विस्तार से लिखा गया खबर पठनीय एवं जानकारीप्रद है।

● **महेश वर्णवाल, टावर चौक, भागलपुर**

पाप धोती है भाजपा

संपादक महोदय,

जिस प्रकार केवल सच टाइम्स पत्रिका का संपादकीय लिखा जाता है उससे काफी जानकारी भी मिलती है। नवम्बर 2023 अंक में आपका संपादकीय **''अपराध एवं पाप धोती है** BJP'' में आपने भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के भाजपा में शामिल होने पर विपक्षियों द्वारा लगाये गये आरोप पर सटीक समीक्षा की है। विभिन्न पार्टियों के नेता भाजपा में आने के बाद गलत करते अब तक नहीं पकड़े गये है की बात को भी प्रमुखता से लिखा गया है। आपका संपादकीय बेबाक एवं पर्दाफास करने वाली रहती है। ED, CBI, IT का इस्तेमाल हो रहा है की राजनीति भी हो रहा है की बात को भी गंभीरता पूर्वक प्रकाशित किया गया है।

● **परमेश्वर दयाल, राजा बाजार, पटना, बिहार**

सुप्रीम कोर्ट

मिश्रा जी,

''दिल्ली के प्रदूषण से निपटने के लिए कैसे जूझ रहा है सुप्रीम कोर्ट'' खबर में उमंग पोद्दार ने दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण पर बेबाक समीक्षा की है। यह समस्या प्रतिवर्ष बढ़ता ही जा रहा है और हजारों कल-कारखानों में प्रदूषण की समस्या पर भी सुप्रीम कोर्ट ने पूरी गंभीरता से लिया है। दिल्ली की आप की सरकार ने कई प्रयास किये और पलाली जलाने के मामले को लेकर भी कई बातें सामने आयी है। वाहन की बढ़ती संख्या भी दिल्ली के प्रदूषण की समस्या में इजाफा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में डीजल पर चलने वाले परिवहन पर अंकुश लगाने का आदेश दिया और सीएनजी को प्राथमिकता दिया। सुप्रीम कोर्ट भी घर्मसंकट में हैं।

● **मनोज यादव, करोल बाग, फिल्मसिटी, दिल्ली**

पनौती

ब्रजेश जी,

केवल सच टाइम्स पत्रिका के नवंबर 2023 अंक में नविन जैन की खबर **''पनौती से नहीं, चुनौती से लड़िए''** में भाजपा एवं कांग्रेस के राजनीतिक बयानों को लेकर एक ही पन्ने में लेकिन सटीक एवं पठनीय खबर को लिखा है। इस अंक का संपादकीय भी मुझे बेहतर लगा। इस अंक में कई खबरें पढ़ने योग्य है और आस्ट्रेलिया ने विश्वकप छठी बार जीतकर परचम लहराया। कानूनी सलाह भी काफी सराहनीय है अगर इसी प्रकार का अन्य क्षेत्र का भी स्थायी स्तंभ को प्रकाशित करना चाहिए ताकि पाठको को स्वास्थ्य, सौन्दर्य एवं योग का भी स्तंभ को दिया जाने से पाठकों की रूचि भी बढ़ेगी। मोदी आज विश्व का सर्वमान्य चेहरा है।

● **कौशल पाठक, सराय रोड़, गया**

अन्दर के पन्नों में

10

28

31

36

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक
'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**
राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)
पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
09431016951, 09334110654

डॉ. सुनील कुमार

शिशु रोग विशेषज्ञ सह मुख्य संरक्षक
'केवल सच' पत्रिका
एवं 'केवल सच टाइम्स'
एन.सी.- 115, एसबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी,
लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना- 800020
फोन- 0612/3504251

श्री सज्जन कुमार सुरेका

मुख्य संरक्षक
'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**
डी- 402 राजेन्द्र विहार, फॉरेस्ट पार्क
भुवनेश्वर- 751009 मो-09437029875

सुधीर कुमार

मुख्य संरक्षक सह निदेशक **''मगध इंटरनेशनल स्कूल''** टेकारी
'' केवल सच '' पत्रिका **एवं '' केवल सच टाइम्स ''**
9060148110
sudhir4s14@gmail.com

श्री आर के झा

मुख्य संरक्षक
'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**
EX. CGM, (Engg.) N.B.C.C
08877663300

एक नजर

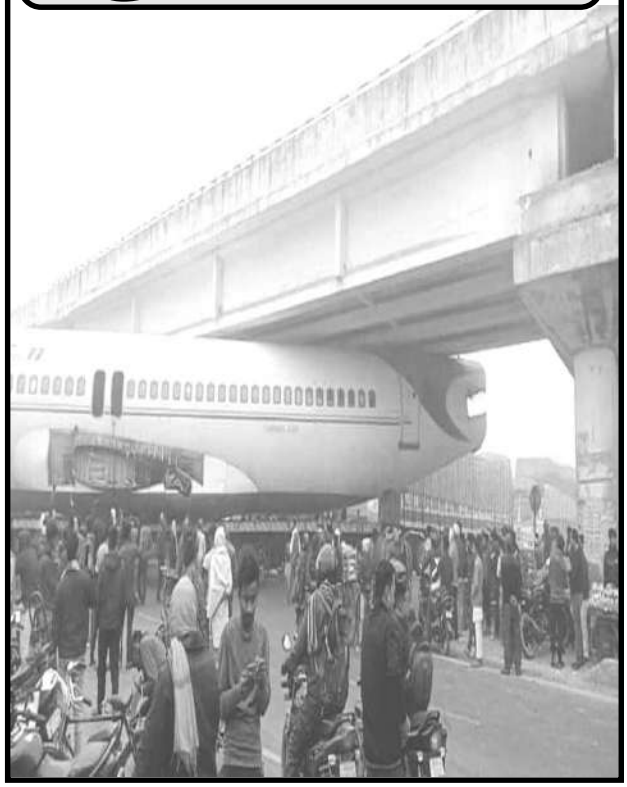

संपादकीय व प्रधान कार्यालयः-

- पूर्वी अशोक नगर, रोड नं:-14, मकान संख्या:- 28/14, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
  e-mail:- kewalsach@gmail.com,
  editor.kstimes@rediffmail.com
  kewalsach_times@rediffmail.com
- स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा जय हिन्द प्रेस कंकड़बाग पटना-800020 से मुद्रित एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। **RNI NO.- BIHBIL/2011/49252**
- पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।
- सभी प्रकार के वाद - विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।
- आलेख पर किसी को कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।
- किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- सभी पद अवैतनिक हैं।
- विज्ञापन की सत्यता की जाँच आप अपने स्तर पर कर लें।
- फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)
- कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।
- **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**
- भुगतान BRAJESH MISHRA को ही करें। किसी प्रतिनिधि को नगद न दें।
- A/C No. :- 20001817444
  BANK :- State Bank Of India
  IFSC Code :- SBIN0003564
  PAN No. :- AKKPM4905A

Contributions/Donations are Invited for the Welfare of Elders/Sr. Citizens for the establishment of
"APNA GHAR" A home for Sr. Citizens of Bihar & Jharkhand Proposed to be Constructed
Under the ageas of " KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN".
KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN
Registered Under the Indian Society Act 21, 1880
East Ashok Nagar, Road No.-14,
Kankarbagh, Patna - 800020
Contact No. :- 09431073769, 9955077308, 9308727077
E-mail :- kewalsachsamajiksansthan33@gmail.com
Reg. No. : 1141 (2009-10), Income Tax No. :12AA/2505-8 | 80 जी (5)/तक०/2013-14/1060-63
APNA GHAR
Now in the State of Bihar & Jharkhand
Help the helpless Elders/Sr. Citizen. For which your
Contribution and Donation are essential.
Your Coopertation in this direction can make a diffrence
in the lives of many Sr. Citizens.
KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN
A/C No. - 0600010202404
Bank Name - United Bank of India
IFSC Code - UTBIOKKB463
Pan No. - AAAAK9339D

कौन लड़ेगा पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव?

● **अमित कुमार**

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन अटकलों को खारिज कर दिया कि पिछले दिल्ली में विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने का सुझाव और उन्हें गठबंधन का संयोजक नहीं बनाए जाने के कारण उन्हें ''मायूसी'' हुई और वे इसको लेकर उन्हें ''नाराजगी'' है। भाजपा के विरोध में विपक्षी दलों को एकजुट करने की पहल करने वाले जदयू नेता ने कहा, ''मुझे कोई मायूसी नहीं हुई, कोई नाराजगी नहीं हुई।'' दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान नीतीश ने दिल्ली और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों क्रमशः अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी द्वारा खरगे के नाम प्रस्तावित किए जाने के बारे में कहा कि बैठक में एक नेता का नाम आया। मैंने शुरू में ही स्पष्ट कर दिया था कि हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं है। सबलोग साथ मिलकर चलें यही हम चाहते हैं। फिर एक और नाम प्रस्तावित किया गया, मैंने कहा कि यह ठीक है।'' भाजपा नेतृत्व वाले राजग में जदयू नेता के विरोधियों ने इस घटनाक्रम की आलोचना करते हुए दावा किया था कि आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो बनर्जी ने वास्तव में नीतीश की कथित प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षाओं को दरकिनार कर दिया है। बैठक के बाद खरगे ने जिस संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया उसमें कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री पद के चेहरे के मुद्दे को ठंडे बस्ते में रखने की इच्छा व्यक्त की थी और इस बात पर जोर दिया था कि इंडिया गठबंधन को पहले पर्याप्त संख्या में लोकसभा सीटें जीतने की जरूरत है। नीतीश से जनवरी तक सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के उनके कथित आग्रह के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हां, मैंने कहा था कि सीट बंटवारे को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। मैं पहले भी इसको लेकर अपने विचार व्यक्त कर चुका हूं। मुझे विश्वास है कि ऐसा सभी राज्यों में सही समय पर कर लिया जाएगा। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सीट बंटवारा सही समय पर हो जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार पर मीडिया पर लगाम लगाने का आरोप लगा चुके नीतीश ने कहा कि आप मीडिया वालों पर नियंत्रण किसी और का है। हम आपकी इज्जत करते हैं और करते रहेंगे। आपलोग खूब आगे बढ़िए। उन्होंने दिवंगत वाजपेयी के प्रति अपने मन में अपार सम्मान की बात करते हुए कहा कि श्रद्धेय अटल जी की सरकार में हम तीन-तीन विभागों के मंत्री थे। वे मुझे बहुत

मानते थे। मुझे बिहार का मुख्यमंत्री बनाने में अटल जी का बहुत बड़ा योगदान है।'' उन्होंने कहा कि उनके प्रति मेरा आदर का भाव हमेशा से रहा है और हम जब तक हैं वो जीवनभर रहेगा। जब तक श्रद्धेय अटल जी प्रधानमंत्री थे तो किसी भी धर्म के माननेवालों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती थी। दिवगंत अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा से संबंधित प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोग जो भी अपनी बात रखते थे वे उसको स्वीकार करते थे। उनके समय में बहुत काम हुआ। हर क्षेत्र में उन्होंने मदद किया, हमने काम भी किया है।

सनद् रहे कि विपक्षी दलों के गठबंधन 'इंडिया' की चौथी बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी से विपक्ष का एक मजबूत संयुक्त उम्मीदवार उतारने पर भी चर्चा हुई थी। बैठक में विपक्षी दल इस बात पर सहमत हुए कि चुनाव में भाजपा का मुकाबला करने के लिए कुछ अलग विचारों की जरूरत है। बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का एक मजबूत संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करने पर भी चर्चा हुई। उल्लेखनीय है कि 2014 के संसदीय चुनावों में, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने वाराणसी से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और वह 3.37 लाख वोटों के अंतर से हार गए थे। वर्ष 2019 में चर्चा थी कि कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि, कांग्रेस ने अजय राय और समाजवादी पार्टी ने शालिनी यादव को मैदान में उतारा था। मोदी ने 60 प्रतिशत से अधिक वोट हासिल कर चुनाव जीता था।

बहरहाल, कांग्रेस नेतृत्व ने अपनी बिहार इकाई के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर सामंजस्य बैठाने पर जोर देने के साथ ही एक कार्ययोजना के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया गया। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, बिहार प्रभारी मोहन प्रकाश, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और कई अन्य नेता मौजूद थे। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता 29 दिसंबर को पार्टी की राष्ट्रीय गठबंधन समिति की बैठक में अपनी बात रखेंगे और उसके आधार पर यह समिति राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल (यूनाइटेड) के साथ सीट बंटवारे को लेकर बातचीत करेगी। कांग्रेस मुख्यालय में हुई इस बैठक में बिहार में संगठन की स्थिति, चुनाव की तैयारियों और सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद खरगे ने एक्स पर पोस्ट किया कि लोकसभा चुनाव संबंधी तैयारियों को लेकर कांग्रेस की बिहार इकाई के नेताओं से चर्चा हुई। बिहार में महागठबंधन सरकार मजबूती से बिहार के लोगों की आशा के अनुरूप काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध हैं। बिहार की तरक्की, खुशहाली और अमन-चैन के लिए कांग्रेस का एक-एक कार्यकर्ता पूरी मेहनत से जन-जन तक जाने और बिहार के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप खरा उतरने को तत्पर है। वही बैठक के बाद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि पहले से स्पष्ट है कि कांग्रेस बिहार में गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। एक कार्ययोजना बनाई गई है, उसे विस्तृत रूप देकर आगे बढ़ेंगे। 29 दिसंबर को गठबंधन समिति की बैठक में सीटों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से अपनी बात रखी जाएगी। खरगे और राहुल गांधी ने विस्तार से बात सुनी। उन्होंने कुछ बातें बताई, हम इस पर रूपरेखा तैयार करके आगे बढ़ेंगे। यह पूछे जाने पर कांग्रेस कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगी? तो उन्होंने कहा कि पिछली बार हम राष्ट्रीय

जनता दल और वाम दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। इस बार जनता दल (यू) भी है। 1-2 सीट आगे-पीछे होने में कोई तकलीफ नहीं है। हम सामंजस्य बनाकर लड़ेंगे और भाजपा को हराएंगे। जब गठबंधन होता है तो रुख में लचीलापन दिखाना होता है। हम गठबंधन समिति के समक्ष अपनी बात रखेंगे और वह दूसरे दलों के साथ बातचीत करेगी। कांग्रेस ने गत् 19 दिसंबर को 5 सदस्यीय राष्ट्रीय गठबंधन समिति का गठन किया था। यह समिति सीट बंटवारे को लेकर सहयोगी दलों के साथ बातचीत करेगी। इस समिति में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश शामिल हैं। कांग्रेस 2019 के विधानसभा चुनाव में बिहार की 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसे सिर्फ किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में सफलता मिली थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार की महागठबंधन की सरकार में कांग्रेस साझेदार है। महागठबंधन के सभी घटक राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल (यूनाइटेड), कांग्रेस और वाम दल राष्ट्रीय स्तर पर बने विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' का हिस्सा हैं।

अभी कलम उठाइये

आपके सामने हो रहे भ्रष्टाचार एवं अपराध की खबर की समीक्षा करें और सरकार सहित पुलिस-प्रशासन तक उसको पहुंचाने के लिए केवल सच पत्रिका के साथ जुड़े। खबर की जानकारी इस नम्बर पर दें

सम्पर्क करें:- 9431073769/9955077308

ई-मेल:- editor.kstimes@rediffmail.com पर भेजें।

आडवाणी-जोशी से आने की बजाय न आने का 'अनुरोध'

इस समय राजनीति में बड़े बड़े दिग्गज बाहर हो रहे हैं। विपक्ष को संसद से बाहर किया जा रहा है तो भाजपा के भीतर मोदी-शाह कैंप के बाहर के नेता बाहर किए जा रहे हैं। शिवराज सिंह, वसुंधरा से लेकर आडवाणी और जोशी सब इसी का उदाहरण हैं। राम मंदिर आंदोलन को चलाने वाले प्रमुख नेता ही अब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से दूर कर दिए गए हैं। जी हां, भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी से इस कार्यक्रम में न आने का 'अनुरोध' किया गया है। अब यह अनुरोध या आदेश यह आप खुद समझ सकते हैं। आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण के लिए ही सन् 1990 में आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या तक रथयात्रा लेकर निकले थे। हालांकि राजनीति के जानकारों की नजर में इस पूरे आंदोलन और

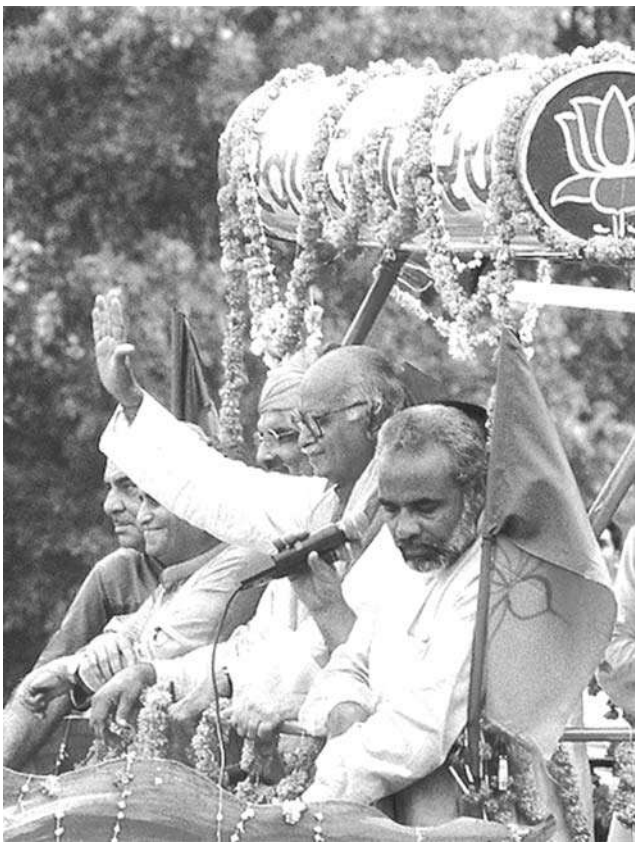

इस रथयात्रा का मकसद पूरी तरह राजनीतिक था। आडवाणी की रथयात्रा को सन् 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने के खिलाफ उनकी मंडल बनाम कमंडल यात्रा की तरह देखा गया। दिलचस्प है कि इस समय के प्रधानमंत्री और रामलला प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य अतिथि नरेंद्र मोदी उस समय आडवाणी के सारथी थे। यानी रथ के संचालन में शामिल थे। लेकिन अब रथी घर बैठाए गए हैं और सारथी ने ही पूरा रथ संभाल लिया है। समाचार एजेंसी भाषा की ओर से जारी खबर के अनुसार राम मंदिर आंदोलन के अग्रणी नेताओं में शुमार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी से उनके स्वास्थ्य और उम्र के कारण अगले महीने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होने का अनुरोध किया गया है। राम मंदिर

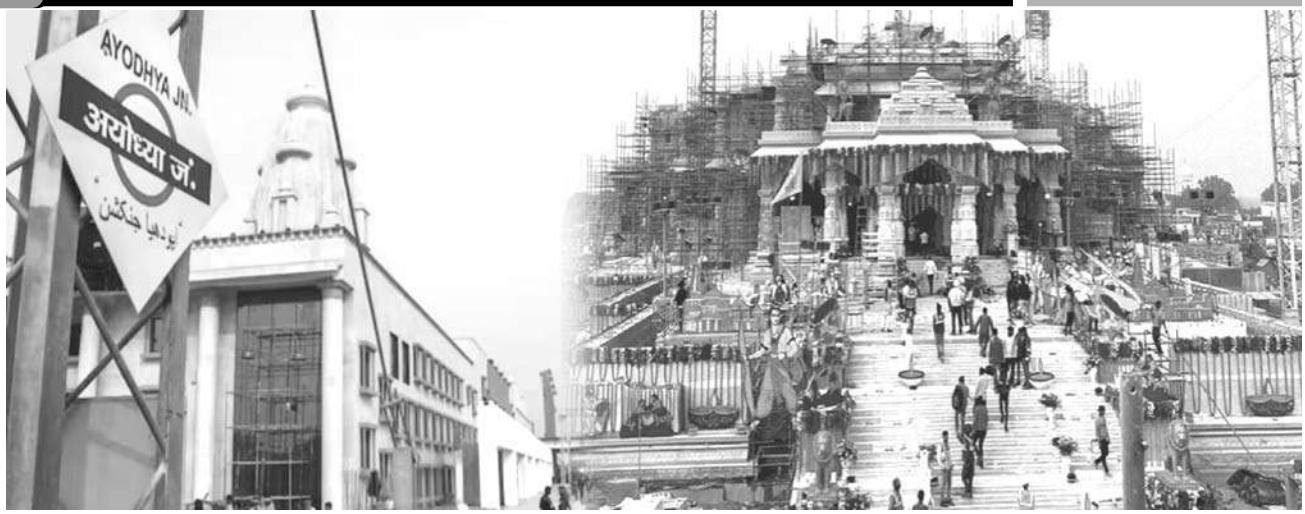

निर्माण के लिए गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोमवार को संवाददाताओं से बातचीत में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आडवाणी और जोशी को आमंत्रित किए जाने के बारे में पूछे गए एक सवाल पर कहा, ''दोनों परिवार के बुजुर्ग हैं और उनकी उम्र को देखते हुए उनसे न आने का अनुरोध किया गया, जिसे दोनों ने स्वीकार कर लिया है।'' राय ने कहा कि 22 जनवरी को अभिषेक समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शामिल होंगे। उन्होंने कहा, ''तैयारियां 15 जनवरी तक पूरी हो जाएंगी और प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजा 16 जनवरी से शुरू होगी जो 22 जनवरी तक चलेगी।'' आमंत्रित लोगों की विस्तृत सूची देते हुए राय ने कहा कि स्वास्थ्य और उम्र

संबंधी कारणों से आडवाणी और जोशी संभवत: अभिषेक समारोह में शामिल नहीं होंगे।

☞ **आडवाणी अब 96 साल के हैं और जोशी अगले महीने 90 साल के हो जाएंगे :-** यहां एक सवाल यह भी उठता है कि जब हमारे यहां 100 साल के बुजुर्ग और अन्य अक्षम व्यक्ति तक वोट डालने आते हैं या उन्हें बुलाया जाता है और उसे प्रचारित किया जाता है। तो फिर एक मंदिर कार्यक्रम में बुजुर्ग के बैठने की व्यवस्था नहीं हो सकती। आपने देखा होगा कि हर चुनाव में कैसे बूढ़े-बुजुर्गों के वोट डालने की तस्वीरें चुनाव आयोग जारी करता है कि देखिए फलां बुजुर्ग या अक्षम व्यक्ति व्हील चेयर पर वोट डालने आया या अपने बूढ़े पिता या मां को बेटा अपनी पीठ पर या कंधे पर बैठाकर पोलिंग बूथ तक लाया।

लेकिन राजनीति का उलट नियम है। शायद इसी को कहते हैं 'वक्ष्त की मार'। आपको याद करा दें कि इस मंदिर आंदोलन और रथयात्रा ने भी देश का बहुत नुकसान किया था। जगह-जगह दंगे हुए थे जिसमें अनगिनत लोग मारे गए। दुकान-मकान जलाए गए। इसी की परिणति 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के रूप में हुई। इसी मंदिर आंदोलन के कंधे पर सवार होकर पहले अटल-आडवाणी-जोशी और फिर मोदी राजनीति के शीर्ष और सत्ता तक पहुंचे।

खैर, इस समय राजनीति में बड़े बड़े दिग्गज बाहर हो रहे हैं। विपक्ष को संसद से बाहर किया जा रहा है तो भाजपा के भीतर मोदी-शाह कैंप के बाहर के नेता बाहर किए जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया से लेकर अब आडवाणी और जोशी सब इसी का उदाहरण हैं। फिर लौटते हैं समाचार एजेंसी भाषा की तरफ। खबर के मुताबिक राय ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा से मिलने और उन्हें समारोह में आमंत्रित करने के लिए तीन सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। उन्होंने कहा, ''विभिन्न परंपराओं के 150 साधु-संतों और छह दर्शन परंपराओं के शंकराचार्यों सहित 13 अखाड़े इस समारोह में भाग लेंगे। कार्यक्रम में लगभग चार हजार संतों को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा 2200 अन्य मेहमानों को भी निमंत्रण भेजा गया है।'' राय ने बताया कि काशी विश्वनाथ, वैष्णोदेवी जैसे प्रमुख मंदिरों के प्रमुखों, धार्मिक और संवैधानिक संस्थानों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा, केरल की माता अमृतानंदमयी, योग गुरु बाबा रामदेव, अभिनेता रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, अरुण गोविल, फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर और प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, प्रसिद्ध चित्रकार वासुदेव कामत, इसरो के निदेशक नीलेश देसाई और कई अन्य जानी-मानी हस्तियां भी प्राण-प्रतिष्ठा समारोह में मौजूद रहेंगी। प्रतिष्ठा समारोह के बाद 24 जनवरी से उत्तर भारत की परंपरा के अनुसार 48 दिनों तक मंडल पूजा होगी। वहीं, 23 जनवरी से आम लोग रामलला के दर्शन कर सकेंगे। राय ने बताया कि अयोध्या में तीन से अधिक स्थानों पर मेहमानों के ठहरने की उचित व्यवस्था की गई है। इसके अलावा विभिन्न मठों, मंदिरों एवं गृहस्थ परिवारों द्वारा 600 कमरे उपलब्ध कराये गये हैं। आगामी 25 दिसंबर से तीन प्रमुख स्थानों पर भंडारा भी शुरू हो जाएगा।

इस बीच, अयोध्या नगर निगम ने प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी शुरू कर दी है। नगर आयुक्त विशाल सिंह ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए शौचालय और महिलाओं के लिए 'चेंजिंग रूम' बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि राम जन्मभूमि परिसर में राम कथा कुंज कॉरिडोर बनाया जाएगा, भगवान राम के पुत्रष्टि यज्ञ से लेकर राम के राज्याभिषेक तक की घटनाओं को मूर्तियों के माध्यम से मनाने के लिए झांकियां सजाई जाएंगी ताकि युवा अगली पीढ़ी श्री राम के जीवन को करीब से समझ सकें। राम कथा कुंज गलियारे को भगवान राम के जीवन पर आधारित 108 प्रसंगों के माध्यम से सजाया जाएगा। इसके अलावा यात्री सुविधा केंद्र के मार्ग पर गलियारे को भी सजाया जाएगा।

राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की अपील

आडवाणी और जोशी प्राणप्रतिष्ठा में न आएं

अयोध्या, ब्यूरो। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख (22 जनवरी) काफी नजदीक आ चुकी है। इस बीच राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बीजेपी के सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से उद्घाटन समारोह में ना पहुंचने की अपील की है। एजेंसी के मुताबिक चंपत राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी स्वास्थ्य और उम्र संबंधी कारणों के चलते उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे। दोनों बुजुर्ग हैं। इसलिए उनकी उम्र को देखते हुए उनसे न आने का अनुरोध किया गया है, जिसे दोनों ने स्वीकार भी कर लिया है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, आडवाणीजी का होना अनिवार्य है, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए हम कहेंगे कि वे कृपया ना आएं। मुरली मनोहर जोशी से मेरी स्वयं बात हुई है। मैं उनसे फोन पर यही कहता रहा कि आप मत आइए और वो जिद करते रहे कि मैं आऊंगा। मैं बार-बार निवेदन करता रहा कि गुरुजी मत आइये। आपकी उम्र और सर्दी... आपने अभी घुटने भी बदलवाए हैं।

बीएचयू में मनुस्मृति रिसर्च प्रोजेक्ट पर बवाल

बीएसएम और एबीवीपी आमने-सामने

● विजय विनीत

बीएचयू जैसे शीर्षस्थ विश्वविद्यालय में ऐसा कोई भी अध्ययन अथवा शोध नहीं होना चाहिए जो समाज को पीछे ले जाने वाला बना दे। आज जब पूरी दुनिया विकास के नए आयाम गढ़ रही है ऐसे में अपने अतीत से चिपककर बैठे रहना उचित नहीं है।

काशी हिन्दू विश्व विद्यालय (बीएचयू) में मनुस्मृति पर रिसर्च के लिए फेलोशिप शुरू किए जाने को लेकर उपजा विवाद गहराने लगा है। एक तरफ भगत सिंह स्टूडेंट्स मोर्चा (बीएसएम) मनुस्मृति पर नए रिसर्च प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा है तो दूसरी ओर बीजेपी का अनुसांगिक संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) 'मनुस्मृति दहन' के विरोध में खड़ा हो गया है। बीएसएम ने सोमवार की शाम कला संकाय के मनुस्मृति की प्रतीक प्रतियां फूंकी तो अभाविप ने इसके विरोध में मंगलवार को कुलपति आवास पर प्रदर्शन किया और भद्दे नारे लगाए। इस दौरान कुलपति और चीफ प्राक्टर पर भद्दी टिप्पणियां भी की गईं। बीएसएम का आरोप है कि, 'सत्ता में बैठे लोगों ने ब्राह्मणवाद सर्वश्रेष्ठ बताने को इस मनुस्मृति रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए भारी-भरकम धनराशि स्वीकृति कराई है। सत्ता की शह पर बीएचयू में जातिवादी और सांप्रदायिक माहौल बनाने के लिए झूठ और भ्रम का वितंडा खड़ा किया जा रहा है।'

बीएचयू के कला संकाय के बाहर भगत सिंह छात्र मोर्चा के दर्जन भर छात्रों के समूह ने सोमवार को सादे पन्ने पर मनुस्मृति के श्लोक लिखकर उसकी प्रतियां फूंकी और आक्रोश व्यक्त किया। मनुस्मृति में ब्राह्मणवाद के महिमामंडन की आलोचना करते हुए ब्राह्मणवाद-मुर्दाबाद, मनुवाद-मुर्दाबाद और जातिवाद को धवस्त करो जैसे नारे भी लगाए गए। भगत सिंह स्टूडेंट्स मोर्चा के फेसबुक पेज पर एक वीडियो भी पोस्ट किया गया है, जिसमें मनुस्मृति की प्रतियां भी जलाई जा रहीं हैं। यह मोर्चा पिछले कई दिनों से मनुस्मृति के खिलाफ मुहिम चला रहा है। दूसरी ओर, मनुस्मृति दहन के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े स्टूडेंट्स भास्कर आदित्य, राजकुमार, मृत्युंजय तिवारी, पतंजली पांडेय आदि ने मंगलवार को कुलपति आवास पर पहुंचकर मनुस्मृति दहन के विरोध में प्रदर्शन किया और भद्दे नारे भी लगाए। इनके विरोध प्रदर्शन का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुलपति और कुलसचिव के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। बीएचयू में मनुस्मृति पर शोध शुरू किए जाने के साथ ही विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं। भगत सिंह स्टूडेंट्स मोर्चा के अलावा बहुजन समाज छात्र संगठन भी बीएचयू में मनुस्मृति पर रिसर्च का विरोध कर रहा है। इनका

आरोप है कि मनुस्मृति में बहुत कुछ ऐसी गलत बातें लिखी गई हैं जो समाज में जातिवाद, वर्ण व्यवस्था और धर्मांधता को बढ़ावा देती हैं।

☞ **मनुस्मृति पर रिसर्च का विरोध क्यों? :-** भगत सिंह छात्र मोर्चा से जुड़ी आकांक्षा आजाद कहती हैं, ष्21वीं सदी में शोषित और वंचित तबके में एक नई रैडिकल चेतना का संचार हुआ है। ऐसे में अतीत के स्याह दौर की याद दिलाती इस किताब की प्रयोज्यता की बात करना दुनिया में भारत की कैसी छवि बनाएगा? बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर ने सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए मनुस्मृति की प्रतियां फूंकी थी। मौजूदा समय में वो समस्याएं जस की तस हैं। महिलाओं और शूद्रों के साथ भेदभाव व असमानता बरकरार है। डा.आंबेडकर हिन्दू धर्म की बुराइयों पर सीधे वार करते थे और कहते थे कि मैं हिन्दू धर्म में पैदा हुआ हूं लेकिन इस धर्म में मरूंगा नहीं। हिन्दू धर्म समानता और स्वतंत्रता का विरोधी है। उन्होंने मनुस्मृति में वर्णित चारो वर्ण व्यवस्था का जमकर विरोध किया और बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था।' मनुस्मृति को लेकर दलित और पिछड़े वर्ग का प्रबुद्ध तबका दशकों से विरोध करता आ रहा है। दरअसल, इस पुस्तक में दलितों और महिलाओं के बारे में कई ऐसे श्लोक हैं जिनकी वजह से अक्सर विवादों का जन्म होता है। इतिहासकारों के मुताबिक, स्मृति का मतलब धर्मशास्त्र होता है। ऐसे में मनु द्वारा लिखा गया धार्मिक लेख मनुस्मृति कही जाती है। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं जिनमें 2684 श्लोक हैं। कुछ संस्करणों में श्लोकों की संख्या 2964है। मनुस्मृति को लेकर मराठी के अग्रणी लेखक प्रो. नरहर कुरूंदकर ने एक पुस्तक लिखी है जिसमें वह अपनी सोच को रेखांकित करते हुए कहते हैं, 'मैं उन लोगों में शामिल हूं जो मनुस्मृति को जलाने में विश्वास करते हैं। ईसा से करीब दो सौ साल पहले मनुस्मृति लिखी गई थी।'

☞ **पहले से पढ़ाई जाती है मनुस्मृति :-** मनुस्मृति को एक खेमा खारिज करता नजर आ रहा है तो दूसरा खेमा एक के बाद एक नए सबूत पेश कर रहा है कि उनकी बात किस तरह सही है? इस बीच बीएचयू के धर्मशास्त्र मीमांसा विभाग ने 'दलितों एवं स्त्रियों को अपमानित करने वाली किताब मनुस्मृति पर शोध फेलोशिप लाकर नए सिरे से विवाद को बढ़ा दिया है। दरअसल, यही वो किताब है जो सौ साल से भी अधिक समय से विवादों में रही है और उसे लेकर बड़े-बड़े आंदोलन भी हुए हैं।' काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र-मीमांसा विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर शंकर कुमार मिश्रा कहते हैं, ष्यह पहला मौका नहीं है जब मनुस्मृति पढ़ाई जा रही है। जब से उनका विभाग बना है तभी से मनुस्मृति समेत कई ग्रंथ कोर्स में हैं और पढ़ाए जाते रहे हैं। उनके विभाग में हर वर्ग के स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। वो पीएचडी भी करते हैं। स्मृतियों में मानवता के लिए उपदेश है। सद-आचरण की शिक्षा से भ्रमित लोगों को उबारने के लिए शोध की जरूरत है। धर्मशास्त्र में कई विचार और विषयों को सरल शब्दों और संक्षेप में जनमानस के सामने रखा जाए ताकि मानव कल्याण की बताई गई बातों से आम जनता परिचित हो। इस मामले में दुष्प्रचार किया जा रहा है। 'भारतीय समाज में मनुस्मृति की प्रयोज्यता' विषय पर शोध की योजना का धर्मशास्त्र मीमांसा विभाग की ओर से प्रस्तुत किया गया है। शोध और शिक्षा में किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस प्रोजेक्ट के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस से मिलने वाले बजट से अनूठे शोध होंगे। सरकारी अधिसूचना के मुताबिक, केंद्र सरकार ने इंस्टिट्यूशंस ऑफ एमिनेंस स्कीम के तहत मनुस्मृति पर रिसर्च करने के लिए देश के दस सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं के लिए एक हजार करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। यह धनराशि रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च की जाएगी। मनुस्मृति का फेलोशिप प्रोग्राम भी इसी का हिस्सा है। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में 'मनुस्मृति की भारतीय समाज पर प्रयोज्यता' विषय

पर रिसर्च कराएगा। रिसर्च फेलोशिप इसी साल31मार्च 2023 को संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय ने शुरू कराई है।

☞ **कहां है विवाद की जड़ :-** मनुस्मृति को लेकर उठे विवाद पर 'न्यूजक्लिक' ने दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के पूर्व प्रोफेसर डाशमशुल इस्लाम से विस्तार से बात की। वह इस पुस्तक के इतिहास को समझाते हुए कहते हैं, 'बाबा साहेब के हिन्दू धर्म को छोड़ने की सबसे बड़ी वजह मनुस्मृति रही। दुर्भाग्य यह है कि हिन्दू कट्टरवाद का हिन्दुओं के बारे में जो एजेंडा है उस पर आज तक कभी कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। मनुस्मृति के समर्थकों की तरह मुस्लिम लीग ने भी गैर-बराबरी और औरतों की हकमारी का एजेंडा चलाया था। मुगल शासक औरंगजेब के जमाने में जो इस्लामी शरीयत (फतवा-ए-जहागीरी) लागू की गई वह पूरी तरह मनुस्मृति से प्रभावित थी। औरंगजेब सोचता था कि हिन्दुओं के साथ वह मुसलमानों को कैसे नियंत्रित करे तो उसने शरीयत के अंदर मनुस्मृति की सारी बातें डाल दी। फतवा-ए-जहागीरी को मनुस्मृति की प्रतिकृति कहा जा सकता है।' प्रो.शमशुल यह भी कहते हैं, 'इस्लाम में औरतों को पुरुषों के बराबर अधिकार दिया गया है। कुरान में कहीं भी पर्दा प्रथा का समर्थन नहीं किया गया है। औरतों को गुलाम बनाकर रखने के लिए मुगल शासकों ने शरिया कानून थोपा। जिस तरह मुस्लिमों के पास कानून की किताब के रूप में शरिया है उसी तरह हिंदुओं के पास मनुस्मृति है। मनुस्मृति बताती है कि ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊपर है इसलिए उसका सम्मान

किया जाना चाहिए। अपने पति की सेवा के बगैर औरतें स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकती हैं। मनुस्मृति और शरिया कानून दोनों ही औरतों और शूद्रों के धार्मिक और शैक्षणिक अधिकारों को खारिज करती है। काशी के पंडितों ने अंग्रेजों को समझा दिया था कि मनुस्मृति हिन्दुओं के जीवन का सूत्रग्रंथ है। इसके प्रचार-प्रसार से ही अपराधों पर अंकुश लग सकता है। अंग्रेजों ने जब इस किताब के जरिये कानूनी मामलों को हल करना शुरू किया तो मनुस्मृति चर्चित हो गई।'

☞ **'पाखंडियों की संरक्षक है मनुस्मृति'** :- इतिहास के पन्नों को पलटने से पता चलता है कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले मनुस्मृति को चुनौती दी और खेतिहर किसानों, मजदूरों, वंचित तबके के लोगों की हालत देखकर उन्होंने ब्राह्मणों की आलोचना की। इसके बाद 25 जुलाई, 1927 को बाबा साहेब डा. भीमराव आंबेडकर ने महाराष्ट्र के कोलाबा में मनुस्मृति को जलाया। फिर देश में कई स्थानों पर मनुस्मृति जलाई गई। बाबा साहेब कहा करते थे कि मनु की जाति व्यवस्था एक बहुमंजिली इमारत की तरह है जिसमें एक से दूसरी मंजिल में जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं होती है। मनुस्मृति में कर्म को विभाजित करने के बजाय काम करने वालों को ही बांट दिया गया। उनका मानना था कि जाति व्यवस्था और पाखंडियों की संरक्षक मनुस्मृति है। आजादी के बाद साल1970 में कांशीराम ने बामसेफ बनाकर इस पुस्तक का विरोध किया। कांशीराम का भी मानना था कि मनुस्मृति की वर्ण व्यवस्था के चलते भारतीय समाज को हजारों जातियों में बांट दिया गया। हाल के दिनों में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने मनुस्मृति का कई मंचों पर विरोध किया है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में औरतों व शूद्र जातियों के उत्पीड़न और अपमानजनक चित्रण की उन्होंने आलोचना की तो हर तरफ बहस छिड़ गई। मनुस्मृति को लेकर एक बड़ा विवाद उस समय भी खड़ा

हुआ था जब दिल्ली उच्च अदालत की न्यायाधीश प्रतिभा सिंह ने फिक्की द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में इस पुस्तक की जमकर तारीफ की तो उनकी जबर्दस्त आलोचना हुई। न्यायाधीश प्रतिभा का कहना था कि मनुस्मृति 'महिलाओं को सम्मानजनक दर्जा देती है।' मनुस्मृति की वकालत करने वालों का मानना है कि मनु ने विश्व कल्याण के लिए ये किताब लिखी। वह कानून विशेषज्ञ थे। मनुस्मृति का समर्थन करने वाले दावा करते हैं कि यह पांचवा वेद है जो समाज के कल्याण की बात करती है। इस पुस्तक का अनादर किया जाना ठीक नहीं है। इस बीच मनुस्मृति की तरफदारी करने के लिए धर्मगुरुओं ने भी दुनिया को बताना शुरू कर दिया कि इस पुस्तक में वेद का सारांश है। इस मुद्दे पर बनारस के वरिष्ठ पत्रकार राजीव मौर्य कहते हैं, 'बीएचयू अब आरएसएस का गढ़ बन गया है। यही वजह है कि मनुस्मृति पर रिसर्च के नाम पर भारी-भरकम धनराशि स्वीकृत की गई है। दुनिया जानती है कि भारत में जब बौद्ध धर्म का फैलाव होने लगा तो मनुस्मृति के जरिये ही ब्राह्मणों ने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए मिथक रचना शुरू कर दिया कि उनका स्थान समाज में सबसे ऊपर है। उनके लिए अलग और दूसरों के लिए अलग नियम हैं। महामना मदन मोहन मालवीय की बगिया में समाज को जाति और धर्म के खांचे में बांटने का ढकोसला बंद होना चाहिए।'

☞ **नफरत पैदा करेगा मनुस्मृति पर रिसर्च** :- मनुस्मृति के शोध पर उपजे विवाद पर 'न्यूजक्लिक' ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के सामाजिक परिष्करण एवं समावेशी नीति अध्ययन केंद्र के एसोसिएट प्रोफेसर डा. अमरनाथ पासवान से विस्तार से बात की। डा.पासवान कहते हैं, 'मनुस्मृति का विरोध इसलिए भी जायज है क्योंकि इस पुस्तक ने सौ साल से औरतों और शूद्र जातियों को अपमानित किया है और उनकी तरक्की भी रोकी है। इस तबके को आर्थिक और सामाजिक तौर पर स्थायी रूप से गुलाम बनाने की कोशिश की है। मनुस्मृति को किसी भी तरीके से धार्मिक अथवा पवित्र पुस्तक नहीं कहा जा सकता। इस मुद्दे को फिर से सैनिटाइज्ड किए जाने से मनुस्मृति को नए सिरे से वैधता मिलेगी और हिन्दू समाज में ऊंच-नीच की खाई गहरी होगी। बाबा साहेब ने मनु की जिस व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर दिया था, शोध के जरिये उसे फिर जिंदा करने की कोई जरूरत नहीं है।' बनारस के वरिष्ठ पत्रकार एवं चिंतक प्रदीप कुमार कहते हैं, 'मनुस्मृति पर शोध की योजना आरएसएस के चिंतन से मिलती-जुलती है। हिन्दुस्तान की आजादी के बाद जब संविधान बनाया जा रहा था उस समय भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिन्दू महासभा के शीर्षस्थ नेता गोलवलकर और सावरकर ने मनुस्मृति के एजेंडे को लागू कराने की कोशिश की थी। हिन्दुत्व के नाम पर सियासत करने वालों को मनुस्मृति आज भी सम्मोहित करती है। दरअसल, यह एक ऐसी पुस्तक है जो महिलाओं के पैरों में हथकड़ी डालती है और मर्दवादी समाज को तमाम दोषारोपणों से आजाद करती है। यही नहीं, यह इकलौती ऐसी पुस्तक है जो आरएसएस की चालाकी और बीजेपी की सियासत के लिए उर्बर जमीन भी तैयार करती है।' प्रदीप कहते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि देश भर में जहां विश्वविद्यालयों के खर्चों में जबर्दस्त कटौती की जा रही है, वहीं आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाली पढ़ाई के लिए टैक्सपेयर का मनमाना धन लुटाया जा रहा है। कोई भी पुस्तक जो समाज में गैर-बराबरी और नफरत पैदा करती हो, ऐसी पुस्तक की पढ़ाई गैर-वाजिब है। बीएचयू जैसे शीर्षस्थ विश्वविद्यालय में ऐसा कोई भी अध्ययन अथवा शोध नहीं होना चाहिए जो समाज को पीछे ले जाने वाला बना दे। आज जब पूरी दुनिया विकास के नए आयाम गढ़ रही है ऐसे में अपने अतीत से चिपककर बैठे रहना उचित नहीं है। (साभार)

World population surged 75 million in year 2023

Data released by the US Census Bureau on Thursday said the world population grew by 75 million people over the past year. On New Year's Day it will stand at more than 8 billion people.

The projected world population on January 1, 2024 is 8,019,876,189, up by 75,162,541 (0.95%) from New Year's Day 2023.At the beginning of 2024, 4.3 births and two deaths are expected worldwide every second, according to the Census Bureau.

☞ **US population growth slows**

The US had a growth rate of 0.53%, just over half the worldwide average figure. It added 1.7 million people and will have a population on New Year's Day of 335.8 million people.The slowest-growing decade currently was in the aftermath of the Great Depression in the 1930s, at 7.3%. If the current pace continues through the end of the 2020s, it could be the slowest-growing decade in US history, at less than 4%, William Frey, a demographer at The Brookings Institution told the AP news agency. "Of course growth may tick up a bit as we leave the pandemic years. But it would still be difficult to get to 7.3%," he said.

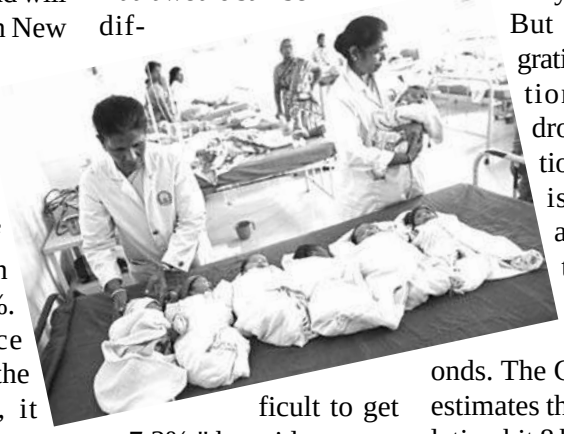

☞ **Migration keeps US population from dropping**

At the start of 2024, the United States is expected to experience one birth every nine seconds and one death every 9.5 seconds. But due to immigration, the population will not drop.Net international migration is expected to add one person to the US population every 28.3 seconds. The Census Bureau estimates the world population hit 8 billion on September 26, 2023. However, according to United Nations Population Division estimates, this occurred on November 15, 2022. The world population growth has been slowing down since the 1960s. It took 12 and a half years for the global population to go from 7 billion to 8 billion. But the Census Bureau says it will take 14.1 years for it to go from 8 billion to 9 billion, and 16.4 years to go from 9 billion to 10 billion, which may occur around 2055.

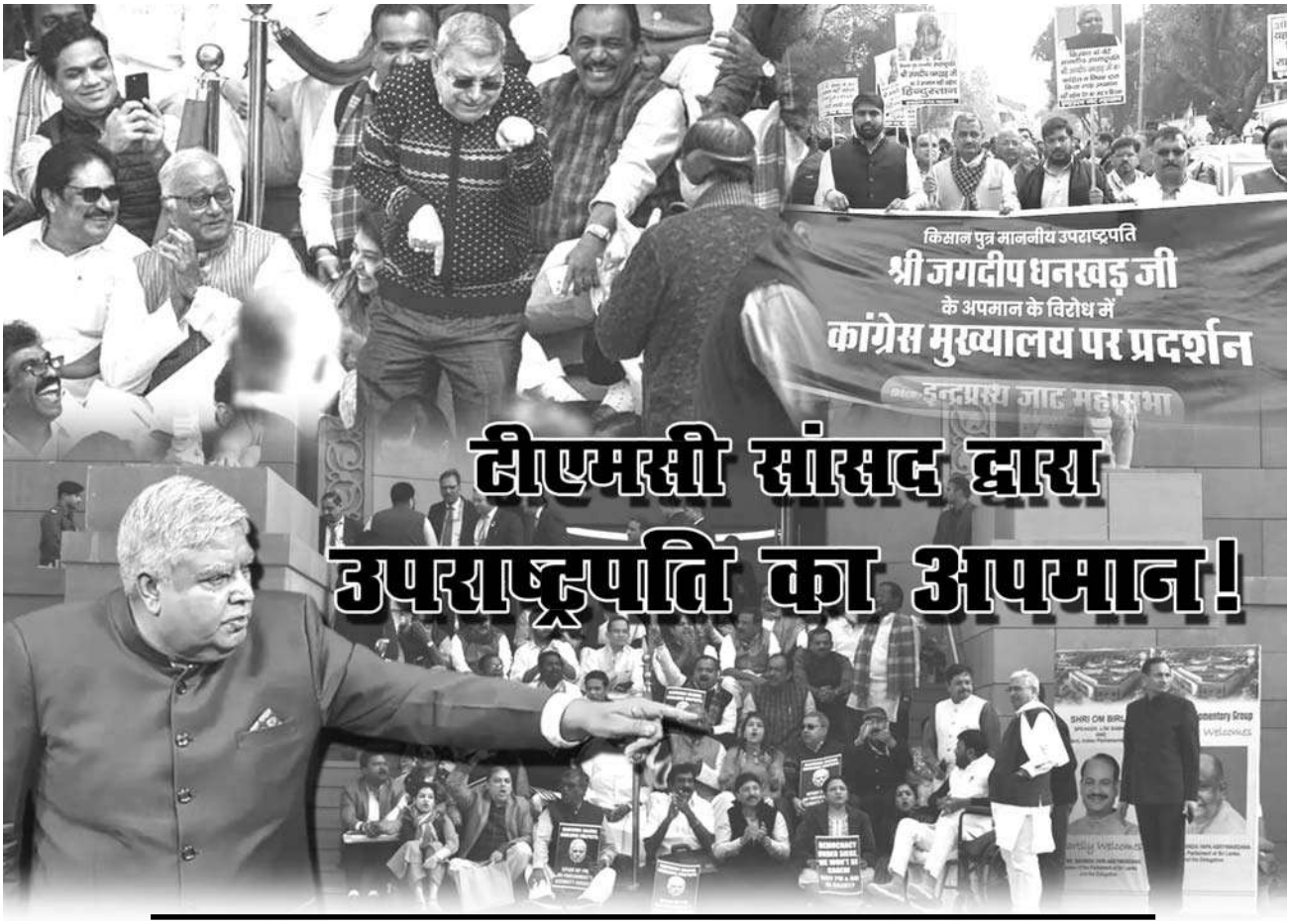

टीएमसी सांसद द्वारा उपराष्ट्रपति का अपमान!

● अमित कुमार

तृणमूल सांसद द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल करने को लेकर पैदा हुए विवाद के बीच, बीजेपी समेत एनडीए के सभी राज्यसभा सांसदों ने उपराष्ट्रपति के साथ एकजुटता दिखाने के लिए एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। एनडीए के 109 सदस्य उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के सम्मान में सदन में एक घंटे तक खड़े रहे। बता दें कि संसद परिसर में उपराष्ट्रपति की नकल करने वाले तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी के एक वीडियो ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। कल्याण बनर्जी विपक्ष के उन 141 सांसदों में शामिल हैं, जिन्हें बीते दिनो संसद सुरक्षा उल्लंघन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग करने पर निलंबित कर दिया गया था। वही नए संसद भवन के मकर द्वार के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान सेरामपुर सांसद कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति की नकल करने लगे। इस दौरान अन्य सांसद हंसते दिखे। और तो और कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस हरकत का वीडियो बनाते दिखे। तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी का मिमिक्री वीडियो 'एक्स' पर शेयर करते हुए बीजेपी नेता संबित पात्रा ने उनकी जमकर आलोचना की। उन्होंने लिखा कि देश याद रखेगा जब देश के उपराष्ट्रपति और संवैधानिक संस्था का माखौल बनाया जा रहा था, तो शहजादा खड़ा होकर वीडियो बना रहा था। भारत तोड़ने वालों का साथ लेकर भारत जोड़ने का स्वांग रचने वालों का मुख्य एजेंडा, जोड़ना नहीं तोड़ना ही है। घमंडियों के घमंड का अंत 2024 में देश की जनता अवश्य करेगी। दूसरी तरफ टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने सफाई दी है कि उनका किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने मिमिक्री को एक आर्ट करार दिया। बनर्जी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के अंदर विपक्षी नेताओं की नकल उतारी

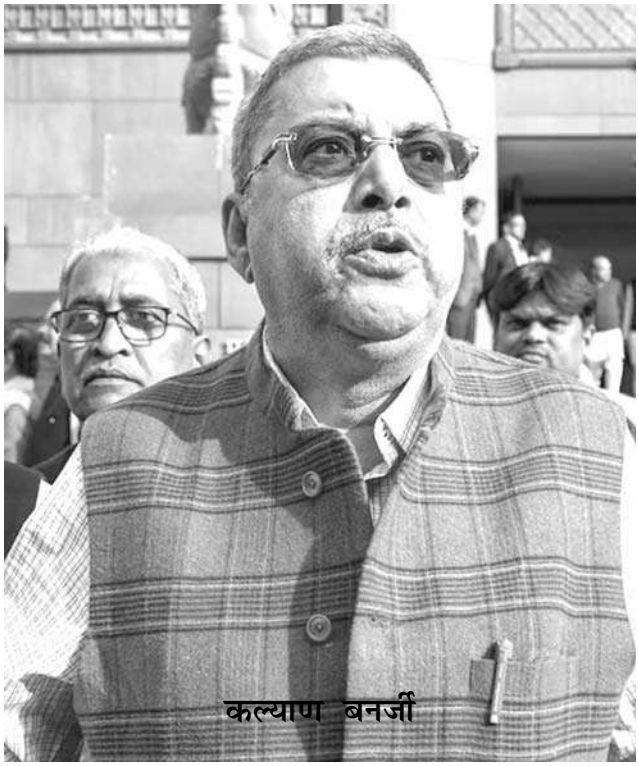
कल्याण बनर्जी

थी। उन्होंने यह भी कहा है कि वह राज्यसभा सदस्य नहीं हैं। उन्हें नहीं पता कि धनखड़ उच्च सदन में कार्यवाही कैसे करते हैं। बता दें कि कल्याण बनर्जी पश्चिम बंगाल की श्रीरामपुर लोकसभा सीट से टीएमसी सांसद हैं।

गौरतलब हो कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान पर संसद में जमकर घमासान हुआ। राज्यसभा में सभापति धनखड़ ने इस पर विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाए। इस बीच उनकी जाति भी मुद्दा बन गई। दूसरी ओर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि इस मामले को जाति का रंग दिया जा रहा है। 11 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने सुरक्षा चूक के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग की। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद परिसर में कुछ सांसदों की ओर से 'अशोभनीय आचरण' किए जाने की ओर से इशारा करते हुए कहा कि सिंह को इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि उन्हें कितनी पीड़ा हुई है। उन्होंने कहा कि आपकी चुप्पी मेरी कानों में गूंज रही है। नेता प्रतिपक्ष की चुप्पी मेरी कानों में गूंज रही है। सबको पता है क्या हो रहा है। आपको अंदाजा होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, हरकतें करता हैं। ये संस्कार हैं क्या आपके। यहां तक स्तर आ गया क्या? इस दौरान सत्ता पक्ष के सदस्य अपने स्थानों पर खड़े

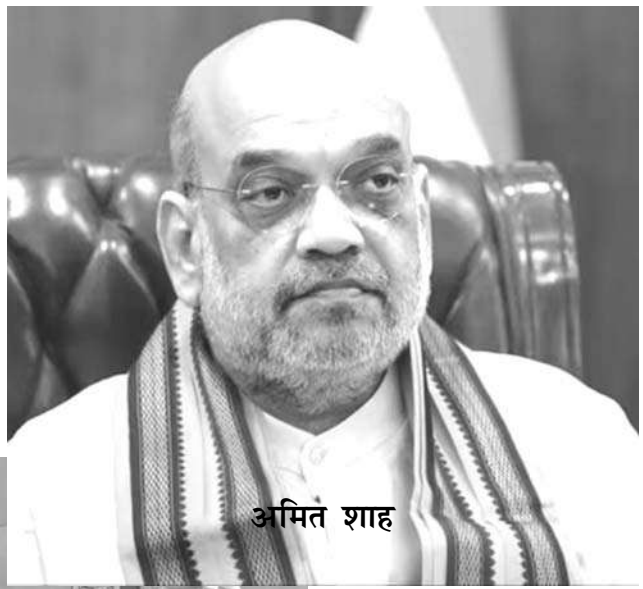
अमित शाह

हो गए। धनखड़ ने कहा कि 'दिग्विजय सिंह जी, मेरी बात सुन लीजिए। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, मेरे समाज की, मेरे वर्ग की... नहीं... मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में।' उन्होंने कहा कि मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है तो मैं सहन करता हूं। खून के घूंट पीता हूं। पर मैं यह बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा को मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना

मेरा काम है। इस पद की गरिमा बनाए रखना मेरा काम है। सभापति ने सिंह से कहा कि वह अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं आपकी सुनता यदि आप एक फोन उठाते और मेरे से कहते। अपने बीच दशकों तक फोन से वार्तालाप होता रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई... पद की गरिमा गिर गई... मेरे समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को बेइज्जत कर दिया और आप चुप रहे। आपके अध्यक्ष चुप रहे। इसके बाद सभापति ने कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले, दूसरी बार के स्थगन के बाद जैसे ही सदन की कार्यवाही आरंभ हुई, द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) सदस्य तिरूचि शिवा ने कुछ 'बेबुनियाद आरोपों' का उल्लेख किया और आसन से कहा कि इसे प्रमाणित किया जाना चाहिए। सभापति जगदीप धनखड़ ने शिवा से कहा कि यदि वे बेबुनियाद आरोपों को लेकर इतने ही सजग हैं तो उन्हें आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। सभापति ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे से आग्रह किया कि बतौर नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष वह विपक्षी सदस्यों को इस प्रकार का आचरण करने से रोकें। इसी समय विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरु कर दिया। खरगे अपनी सीट पर खड़े होकर कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन सभापति ने कार्यवाही 11.45 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। हालांकि, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि वह सदन में व्यवस्था बनाएंगे। इससे पहले, पहली बार के स्थगन के बाद 11.15 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही आरंभ हुई, विपक्षी सदस्यों ने हंगामा आरंभ कर दिया। सभापति धनखड़ अपनी सीट पर बैठे भी नहीं और उन्होंने कार्यवाही 11.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

बताते चले कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का नाम लिए बगैर कहा कि उन्हें यह जानकर बहुत धक्का लगा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग संसद में जाति का नाम लेकर कहते हैं कि उनका अपमान किया गया है। उन्होंने शीतकालीन सत्र में 146 विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ जंतर-मतर पर आयोजित विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन में यह दावा भी किया कि विपक्षी गठबंधन 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस' (इंडिया) के घटक दलों के सभी नेता एकजुट हो गए हैं और अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अकेले कुछ नहीं कर सकते। खरगे ने कहा कि मुझे इस बात का बहुत धक्का लगा कि संवैधानिक पद पर बैठे लोग यह कहते हैं कि वे किसी जाति से संबंध रखते हैं और उनका अपमान किया गया। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर आपकी यह हालत यह है तो मेरे जैसे दलित की क्या हालत होगी? राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद परिसर में उनकी, तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा नकल उतारे जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए उच्च सदन में कहा कि संसद परिसर में उनकी नकल उतारकर किसान समाज और उनकी जाति (जाट) का अपमान किया गया है। खरगे ने कहा कि सभी विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं। अब मोदी जी अकेले कुछ नहीं कर सकते। विरोध प्रदर्शन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि देश की संसद को और प्रजातंत्र को बचाने के लिए जो कुछ कीमत देनी पड़ेगी, वो कीमत चुकाने के लिए सभी विपक्षी दल तैयार हैं। उन्होंने दावा किया कि दलित, आदिवासी, युवा और किसान सभी दुखी हैं तथा भारतीय जनता पार्टी सभी समस्याओं की जड़ है। पवार ने कहा कि प्रजातंत्र पर हमला करने वाली सांप्रदायिक शक्ति को हम सत्ता से दूर करेंगे। वही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारे जाने से जुड़े विवाद का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि धनखड़ यह मुद्दा उठाकर संसद में जातिवाद ले आए। खरगे ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संसद से जुड़े विषयों पर सदन के बाहर बोल रहे हैं जिससे उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद परिसर में उनकी, तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा नकल उतारे जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए उच्च सदन में कहा था कि संसद परिसर में उनकी नकल उतारकर किसान समाज और उनकी जाति (जाट) का अपमान किया गया है। विपक्षी सांसदों ने दोनों

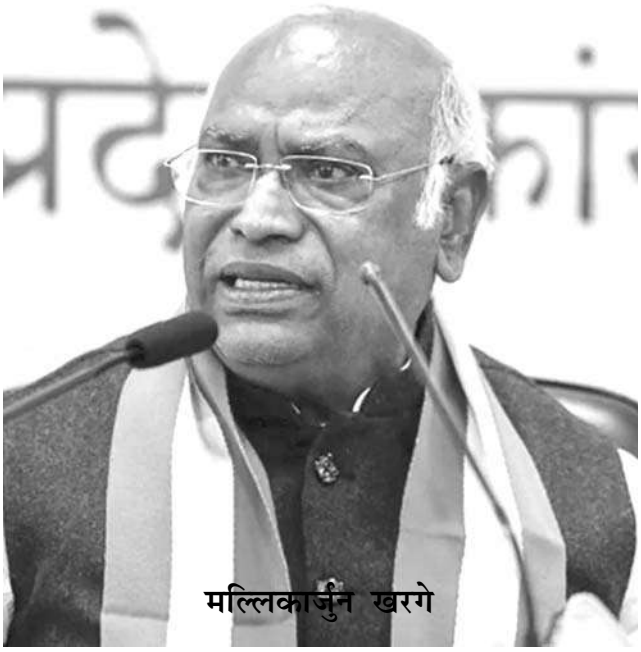
मल्लिकार्जुन खरगे

सदनों से 140 सदस्यों के निलंबन पर विरोध जताते हुए संसद भवन से एक मार्च निकाला जो विजय चौक पर संपन्न हुआ। खरगे की अगुवाई में विपक्षी सांसदों ने संसद भवन से विजय चौक तक पैदल मार्च किया। खरगे ने कहा कि यह निलंबन के खिलाफ हमारा प्रदर्शन है। सरकार और मोदी जी यह नहीं चाहते कि सदन चले। उन्होंने कहा कि मैं माफी चाहता हूं कि सभापति जी एक मुद्दा उठाकर संसद में एक तरीके से जातिवाद ले आए। लोकतंत्र में बात करना हमारा हक है। हम चुने हुए सदस्य हैं और लोगों की भावना को बताना हमारा कर्तव्य हैं, हम वही कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम लोकसभा में, संसद की सुरक्षा में सेंध की घटना से जुड़ा विषय उठाना चाहते थे कि यह क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। हम चाहते थे कि सरकार सदन को इस बारे में बताए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों सदन में नहीं आए। वे, सदन में जिन बातों को कहना है, उन्हें बाहर बोल रहे हैं।

बहरहाल, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को फोन किया और संसद परिसर में कुछ सांसदों की ओर से 'अशोभनीय आचरण' करते हुए उनका मजाक उड़ाए जाने पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मैं भी करीब 20 सालों से इस तरह का अपमान सह रहा हूं। उपराष्ट्रपति सचिवालय की ओर से सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर किए गए एक पोस्ट में धनखड़ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का फोन आया। उन्होंने कुछ माननीय सांसदों की ओर से कल, वह भी पवित्र संसद परिसर में की गई ड्रामेबाजी पर बहुत दुख व्यक्त किया। पोस्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने धनखड़ से कहा कि वह स्वयं करीब 20 वर्षों से इस तरह के अपमान का सामना कर रहे हैं और यह सिलसिला अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि भारत के उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के साथ यह होना, वह भी संसद में, दुर्भाग्यपूर्ण है। धनखड़ ने प्रधानमंत्री से कहा कि कुछ लोगों की हरकतें उन्हें अपना कर्तव्य निभाने और संविधान में निहित सिद्धांतों को बनाए रखने से नहीं रोक सकतीं। उन्होंने कहा मैं अपने दिल की गहराई से उन मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध हूं। कोई भी अपमान मुझे अपना रास्ता बदलने के लिए मजबूर नहीं करेगा। संसद की सुरक्षा में सेंध की घटना पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर हंगामा करने पर दोनों सदनों से 90 से अधिक विपक्षी सदस्यों को निलंबित किए जाने के विरोध में विपक्ष के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया और सदन की 'मॉक कार्यवाही' का आयोजन किया था। निलंबित सांसदों ने संसद के नए भवन के मकर द्वार पर ध रना दिया। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्य कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, सदनों की कार्यवाही का संचालन किए जाने की नकल उतारी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बनर्जी द्वारा कार्यवाही के संचालन की नकल किए जाने का मोबाइल फोन से वीडियो बनाते देखे गए। राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष की नकल उतारे जाने की घटना पर गहरी आपत्ति जताते हुए इसे अस्वीकार्य करार दिया था। वही इस घटना को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि संसद परिसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को जिस तरह अपमानित किया गया, उससे वे बेहद व्यथित हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधि अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन उनकी अभिव्यक्ति शालीन तथा मर्यादा के दायरे में होनी चाहिए। राष्ट्रपति का यह बयान सांसदों के निलंबन के खिलाफ संसद की सीढ़ियों पर विपक्षी सदस्यों के विरोध प्रदर्शन के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा धनखड़ की नकल उतारे जाने के एक दिन बाद आया है। मुर्मू ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि संसद परिसर में हमारे माननीय उपराष्ट्रपति को जिस तरह से अपमानित किया गया, उससे मैं बेहद व्यथित हूं। निर्वाचित प्रतिनिधि अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन उनकी अभिव्यक्ति शालीन एवं मर्यादा के दायरे में होनी चाहिए। हमारी संसदीय परंपराएं हैं जिन पर हमें गर्व है और भारत में उन्हें बरकरार रखने की आशा करते हैं।

द्रोपदी मुर्मू

शराबबंदी पर सर्वे क्यों करा रही है बिहार सरकार?

● **मनीष कुमार**

जातिवार गणना के बाद बिहार में अब शराबबंदी पर सर्वे की तैयारी है। इसके जरिए नीतीश सरकार यह जानना चाहती है कि कहीं शराबबंदी को लेकर किसी तबके में नाराजगी तो नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी को अपनी बड़ी उपलब्धि गिनाते आए हैं। उनका कहना है कि वो इसे कभी वापस नहीं लेंगे। बावजूद इसके सरकार शराबबंदी पर सर्वे कराने की तैयारी कर रही है। कई जानकार इस सर्वे में चुनावी डर का संकेत देखते हैं। उनका मानना है कि शायद नीतीश सरकार को डर है कि 2024 के लोकसभा चुनाव या अगले विधानसभा चुनाव में कहीं यह शराबबंदी का मुद्दा भारी न पड़ जाए।

☞ **सर्वे का मकसद :-** अप्रैल 2016 में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से इसके प्रावधानों और लागू करने के तरीके पर बार-बार सवाल उठाए गए। इसी वजह से इस कानून में कई बार संशोधन किए गए। पिछले महीने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नशा मुक्ति दिवस के मौके पर जातिगत गणना की तरह ही घर-घर जाकर शराबबंदी पर सर्वेक्षण किए जाने की घोषणा की। सर्वे से यह पता चल सकेगा कि कितने लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं और कितने नहीं। मद्य निषेध विभाग ने इसके लिए एक प्रश्नावली तैयार की है। कहा जा रहा है कि इस सर्वे में परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के संबंध में भी जानकारी मांगी जाएगी। बिहार के सभी जिलों में कम-से-कम 2,500 घरों में सर्वे की योजना है। यह काम 12 हफ्ते में पूरा किया जाएगा। राज्य सरकार यह कवायद अपने

खर्च पर करा रही है।

☞ **पहले के सर्वे में क्या पता चला? :-** इससे पहले 2018 में भी एक सर्वेक्षण किया गया था। उसमें डेढ़ करोड़ से ज्यादा लोगों के शराब छोड़ने की जानकारी सामने आई थी। सर्वे के मुताबिक, इन प्रतिभागियों ने बताया कि उन्होंने शराब से बचाए पैसे को सब्जी, कपड़े व दूध जैसी जरूरी चीजें खरीदने पर खर्च किया। इसके बाद दूसरा सर्वे फरवरी 2023 में हुआ, जिसमें राज्य के सभी 38 जिलों के तीन हजार से ज्यादा गांव शामिल किए गए थे। यह सर्वे चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी और जीविका (बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना) ने किया था। इसका सैंपल साइज 10 लाख से ज्यादा था। सर्वे से पता चला कि प्रतिभागियों में 99 प्रतिशत महिलाएं और 92 प्रतिशत पुरुष शराबबंदी के पक्ष में हैं। इसमें भी दो करोड़ से ज्यादा लोगों द्वारा शराब छोड़ देने की बात सामने आई थी। रिपोर्ट के अनुसार, 80 प्रतिशत से ज्यादा लोग शराबबंदी जारी रखने के समर्थन में थे।

☞ **शराबबंदी पर शुरू से ही सियासत :-** इस कानून के लागू होने के बाद से ही विपक्षी दलों ने सीधे-सीधे इसका विरोध नहीं किया। जानकार इसके पीछे राजनीतिक मजबूरी को कारण बताते हैं। हालांकि विपक्ष कानून को लागू करने के तरीके पर सवाल उठाता

रहा है। तब विपक्ष में रहे राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने आरोप लगाया था कि इस कानून के जरिए केवल गरीबों को प्रताड़ित किया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव ने तो शराबबंदी कानून को तुरंत खत्म करने की मांग की थी। तेजस्वी यादव ने भी इसके कारण हो रहे राजस्व के नुकसान का मामला उठाया था। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के संरक्षक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी तो नीतीश कुमार के साथ रहते हुए भी शराबबंदी का विरोध करते रहे। मांझी कई बार कह चुके हैं कि इससे गरीबों का बड़ा नुकसान हुआ है। मांझी कहते हैं कि वर्तमान शराब नीति बहुत ही दोषपूर्ण है। आज चार लाख से ज्यादा लोग शराब पीने और बेचने के आरोप में जेल में बंद हैं। इनमें 80 प्रतिशत दलित और गरीब तबके के हैं। 2025 में अगर मेरी सरकार बनी, तो या तो गुजरात मॉडल लागू कर देंगे या शराबबंदी हटा देंगे। पहले भी लोग पीते थे, अब भी पी रहे हैं। शराबबंदी में तो लोग जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं।

☞ **लोगों के मन की बात जानने की कोशिश क्यों? :-** सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद राज्य में देसी और विदेशी शराब का अवैध धंधा फल-फूल रहा है। शराबबंदी लागू होने के तीन महीने बाद ही गोपालगंज के खजूर बन्नी में जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत हो गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से अब तक इससे 250 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। राज्य के विभिन्न थानों में इस कानून के उल्लंघन से संबंधित करीब साढ़े पांच लाख मामले दर्ज हैं। इनके अलावा करीब आठ लाख

लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अदालतों में शराबबंदी से जुड़े मुकदमों का अंबार लगा है। यही वजह रही कि दिसंबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन चीफ जस्टिस एन।वी। रमन्ना ने इसे दूरदर्शिता की कमी के साथ लागू किया गया कानून बताया था। शराबबंदी लागू करने में लापरवाही बरतने या इससे संबंधित भ्रष्टाचार के आरोप में सैकड़ों पुलिसकर्मियों व सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों को निलंबित किया जा चुका है। ड्रोन के जरिए शराब बनाने के अड्डों की खोज की जा रही है। बरामदगी के आंकड़े और दूसरे राज्यों में माफिया की गिरफ्तारी से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड जैसे राज्यों से अवैध शराब बिहार में लाई जा रही है। शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से इसमें अब तक कई महत्वपूर्ण संशोधन किए जा चुके हैं। अब तो पहली बार पीते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना देकर छोड़ने का प्रावधान हो गया है। पत्रकार संजय सिंह कहते हैं कि जहरीली शराब से होने वाली मौतों, अदालतों में मुकदमों के अंबार और अधिक संख्या में गरीबों-दलितों की गिरफ्तारी को लेकर शुरू से ही सवाल उठते रहे हैं। चुनाव नजदीक आ गया है, तो जाहिर है कि सरकार पर राजनीतिक दबाव तो होगा ही। सर्वेक्षण से इस मुद्दे पर आम लोगों के मूड का पता तो चल ही जाएगा।

☞ **क्या शराबबंदी का मकसद हासिल हुआ? :-** बिहार में शराबबंदी लागू करने में महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि बड़ी संख्या में महिलाओं द्वारा की गई मांग ने इस कानून की राह बनाई। नीतीश कुमार ने 2015 के चुनाव में जीत कर आने पर इसे लागू करने का वादा किया था। इस वादे से उन्हें महिला मतदाताओं का भरपूर समर्थन मिला। महिलाओं का वोट प्रतिशत 59।92 हो गया। सत्ता में लौटते ही नीतीश ने शराबबंदी की घोषणा कर दी। पत्रकार शिवानी सिंह कहती हैं कि यह सच है कि शराबबंदी लागू होने से उन महिलाओं को नई जिंदगी मिली, जिनके पारिवारिक जीवन को शराब ने नरक बना दिया था। उनके साथ घरेलू हिंसा में कमी आई। यह नारी सशक्तीकरण और महिला सुरक्षा की दिशा में वाकई एक ऐतिहासिक कदम था।

☞ **महिलाओं का नजरिया :-** जानकार मानते हैं कि इस कानून के कारण महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक दशा में सुधार भी हुआ है। हालांकि अब इसमें भी संशय नहीं कि अवैध शराब की बिक्री और जहरीली शराब पीने से होने वाली मौतों के कारण इस तबके में नाराजगी भी उभर रही है। पटना की श्यामा देवी कहती हैं कि शराबबंदी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अवैध शराब हर जगह मिल रही है। यह बुरी बात है। यह पुलिस-प्रशासन की विफलता है। केवल नियम बना देने से कुछ नहीं होता है, उसका कड़ाई से पालन भी जरूरी है। इसी तरह किशोरी चौधरी का कहना है कि अब फिर से सड़कों पर शराब पीकर लड़खड़ाते लोग दिखने लगे हैं। जहरीली शराब पीने से लोग मर रहे हैं और इसका खामियाजा परिवार वाले भुगतते हैं। अगर पूरी तरह रोक लगी होती, तो उन्हें जहरीली शराब नहीं मिलती और उनकी जान नहीं जाती। नहीं तो लोग पहले भी पी रहे थे, क्या फर्क पड़ रहा था।

☞ **और कड़ाई या ज्यादा ढील? :-** अवैध शराब की भारी मात्रा में बरामदगी यह बताने के लिए काफी है कि सरकार और प्रशासन, शराब व्यापारियों के सिंडिकेट को तोड़ नहीं पा रही है। इनका नेटवर्क भी पूरी तरह काम कर रहा है। हालांकि इसके लिए पुलिस- प्रशासन से लेकर नेताओं तक पर संलिप्तता के आरोप लगते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद सुशील कुमार मोदी कहते हैं कि सरकार यह बताए कि जब्त की गई 2 करोड़ 16 लाख लीटर शराब राज्य में आई कहां से? हर साल राज्य को दस हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है। अभी तक इसकी क्षतिपूर्ति का विकल्प तक सरकार नहीं खोज पाई है, तो अब सर्वे पर अरबों खर्च करने का औचित्य क्या है। कौन कहेगा कि शराबबंदी गलत है। नीतीश कुमार ने यह कहा था कि जब तक वह सत्ता में हैं, तब तक शराबबंदी जारी रहेगी। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि सर्वे के आधार पर नए उपाय लागू किए जाएंगे। ये उपाय शराबबंदी को और कड़ाई से लागू करने वाले होंगे या ढील देने वाले होंगे, ये तो आने वाले महीनों में पता चलेगा।

Setting Financial Goals for the New Year Using Personal Loans Wisely

As the new year approaches, it's a perfect time to reflect on your financial goals and aspirations. A Personal Loan can serve as a versatile financial tool to help you achieve a wide range of objectives. The strategic use of these loans can set the stage for a financially successful year. In this comprehensive guide, we'll explore ten ways to leverage a Personal Loan wisely in setting and achieving your financial goals for the upcoming year.

☞ **Debt Consolidation :-** One of the most effective ways to start the new year on a financially savvy note is by consolidating high-interest debts. If you find yourself juggling multiple debts, such as credit card balances or payday loans, consider applying for a Personal Loan to consolidate them into a single, more manageable repayment plan. This not only simplifies debt management but also potentially reduces your overall interest payments. Before opting for this option, check the new personal loan's interest rates and compare the aggregate cost of the new loan with the cost of your existing debts.

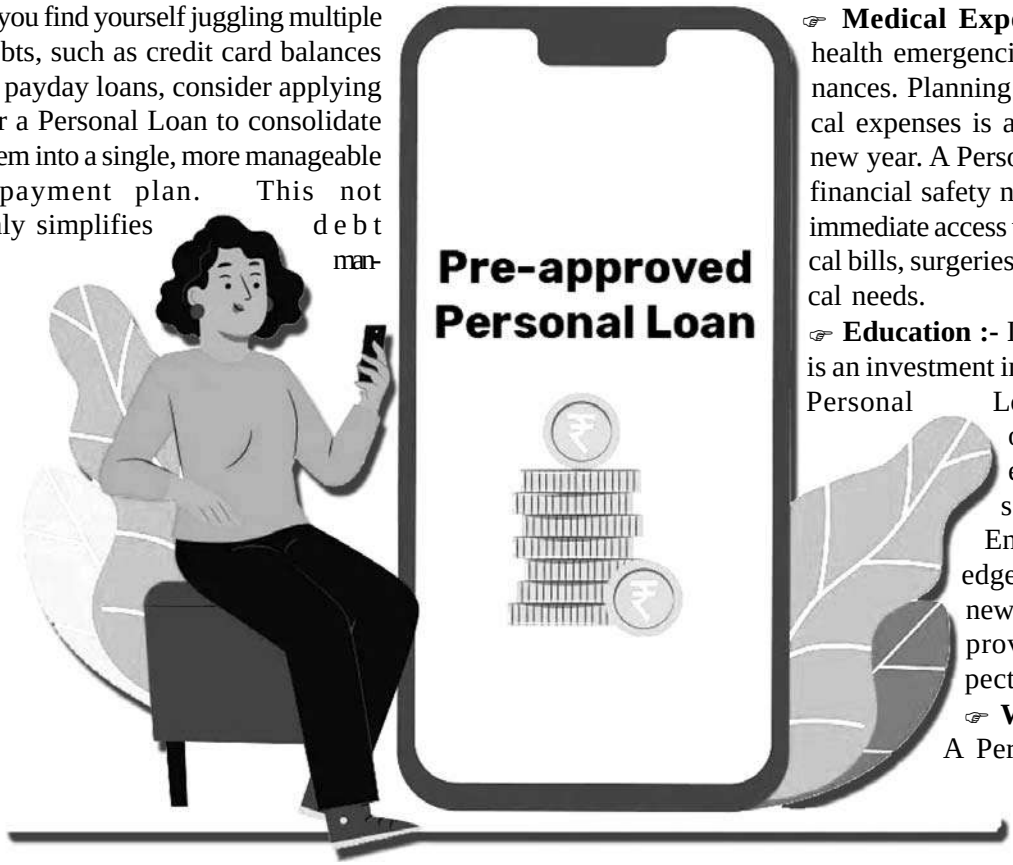

☞ **Home Renovation :-** Investing in your home is an investment in your future. Use a Personal Loan to undertake home renovation projects that enhance both the aesthetic appeal and value of your property. Whether it's a kitchen upgrade, bathroom remodel, or an additional room, a well-utilised Personal Loan can help transform your living space.

☞ **Medical Expenses :-** Unexpected health emergencies can strain your finances. Planning for unforeseen medical expenses is a prudent goal for the new year. A Personal Loan can act as a financial safety net, ensuring you have immediate access to funds to cover medical bills, surgeries, or other urgent medical needs.

☞ **Education :-** Investing in education is an investment in yourself. Apply for a Personal Loan to fund skill development courses, higher education, or professional certifications. Enhancing your knowledge and skills can open new opportunities and improve your career prospects.

☞ **Wedding Expenses :-** A Personal Loan can ease the financial burden associated with wedding expenses. From

venue bookings to catering and entertainment, it can help you celebrate your special day without compromising on your desires.

☞ **Travel and Vacation :-** Create lasting memories by planning your dream vacation for the upcoming year. Whether it's an international adventure or a domestic getaway, a Personal Loan can provide the necessary funds to make your travel goals a reality.

☞ **Business Start-up or Expansion :-** For entrepreneurs and small business owners, the new year might be the perfect time to kickstart a new business venture or expand existing operations. A Personal Loan can serve as a valuable source of capital, covering initial setup costs or providing working capital to fuel growth.

☞ **Emergency Repairs :-** Unforeseen emergencies like car repairs or home appliance breakdowns can disrupt your daily life and even your finances. Having a Personal Loan enables you to quickly access funds when urgent repairs are needed, preventing further financial strain.

☞ **Special Occasions :-** Celebrate life's special moments in style. Whether it's an anniversary, birthday, or milestone, a well-managed Personal Loan can provide the financial means to make these occasions memorable.

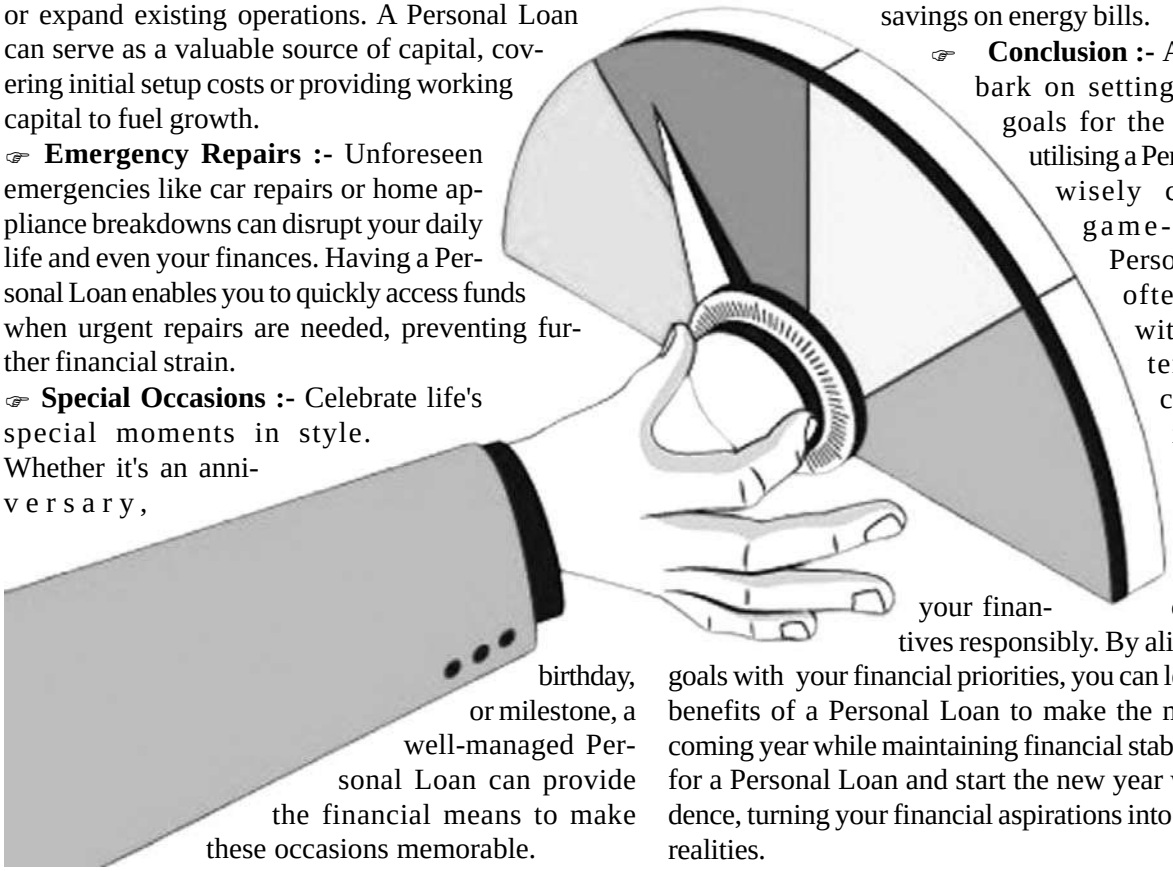

☞ **Emergency Fund Augmentation :-** Strengthen your financial safety net by using a Personal Loan to boost your emergency fund. Having a robust emergency fund ensures you're prepared for unexpected financial challenges, providing peace of mind and stability.

☞ **Green Initiatives at Home :-** Consider applying for a Personal Loan to invest in eco-friendly home improvements. Whether it's installing solar panels, improving insulation, or upgrading to energy-efficient appliances, such initiatives not only contribute to a sustainable environment but can also lead to long-term cost savings on energy bills.

☞ **Conclusion :-** As you embark on setting financial goals for the new year, utilising a Personal Loan wisely can be a game-changer. Personal Loans often come with flexible terms and competitive interest rates, empowering you to achieve your financial objectives responsibly. By aligning your goals with your financial priorities, you can leverage the benefits of a Personal Loan to make the most of the coming year while maintaining financial stability. Apply for a Personal Loan and start the new year with confidence, turning your financial aspirations into achievable realities.

राष्ट्रवाद की संकुचित भावना को धोखा देते तीन नए आपराधिक कानून

पारसा वेंकटेश्वरराव जूनियर लिखते हैं कि, तीन नए आपराधिक कानूनों के गुण या दोष जो भी हों, बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि कानून और व्यवस्था मशीनरी उनका इस्तेमाल कैसे करेगी और अंततः अदालतें उनकी व्याख्या कैसे करती हैं। मौजूदा संरचनाओं को उलटने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रबल महत्वाकांक्षा पिछले नौ सालों और उससे अधिक समय से उनके शीर्ष पर रहने की पहचान है। तीन नए कानूनों ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता अधिनियम, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को हिंदी शीर्षक के तहत भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक (बीएसबी) के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में तीन विधेयकों पर बहस का जवाब देते हुए एक दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी राजनेता की तरह तर्क दिया कि औपनिवेशिक युग के कानून केवल ब्रिटिश हितों की रक्षा के लिए थे और इसलिए इन नए कानूनों का मसौदा तैयार किया गया है ताकि न्याय दिया जा सके, न कि केवल सजा जैसा कि पहले के कानूनों की मंशा थी। शाह अपनी पक्षपातपूर्ण बयानबाजी में लगे रहे। उन्होंने कहा, ''मोदीजी के नेतृत्व में, मैं ऐसे विधेयक लाया हूं जो भारतीयता, भारतीय संविधान और लोगों की भलाई पर जोर देते हैं। इसलिए संविधान की भावना के अनुरूप कानूनों में बदलाव किया जा रहा है।" यह सामान्य ज्ञान है कि भारतीय संविधान की भावना एंग्लो-सैक्सन है, जिसमें स्वतंत्रता, लोगों के अधिकारों और लोकतांत्रिक शासन पर जोर दिया गया है, जो कि मोदी के अत्यधिक दावे के बावजूद कि भारत लोकतंत्र की जननी है, भारतीयों के पास अपने 5,000 साल पुराने इतिहास में कभी नहीं था। यह कहने के बाद भी, कानूनों में बदलाव, यदि वे बेहतरी के लिए हैं, तो हमेशा स्वागतयोग्य हैं। देखने वाली बात कानूनों की मंशा और भावना है। यदि यह केवल पुराने शब्दों का पुनर्लेखन है, तो यह शाह और मोदी की तरफ से एक माफी योग्य पाप है। यह राजनेताओं की दुर्बलता है कि वे अपने द्वारा किए गए छोटे कामों का श्रेय खुद को देना चाहते हैं और उन बड़े कामों का जो उन्होंने नहीं किए हैं।

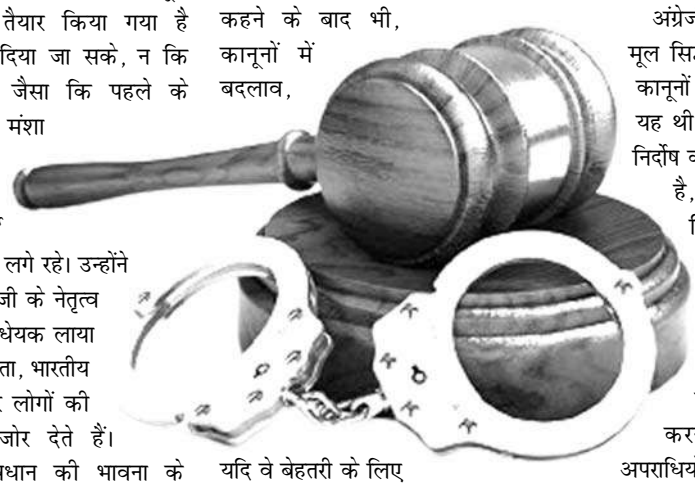

अंग्रेजी आम कानून का मूल सिद्धांत, औपनिवेशिक कानूनों के पीछे की भावना यह थी कि न्याय का अर्थ निर्दोष को दंडित नहीं करना है, यह स्वीकार करना कि कोई व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक कि अन्यथा साबित न हो जाए और एक निर्दोष व्यक्ति को दंडित करने के बजाय सौ अपराधियों को रिहा कर देना। भारत में कई लोग जो आजादी से पहले और बाद में औपनिवेशिक कानूनों के साथ रहे हैं, उनके लिए

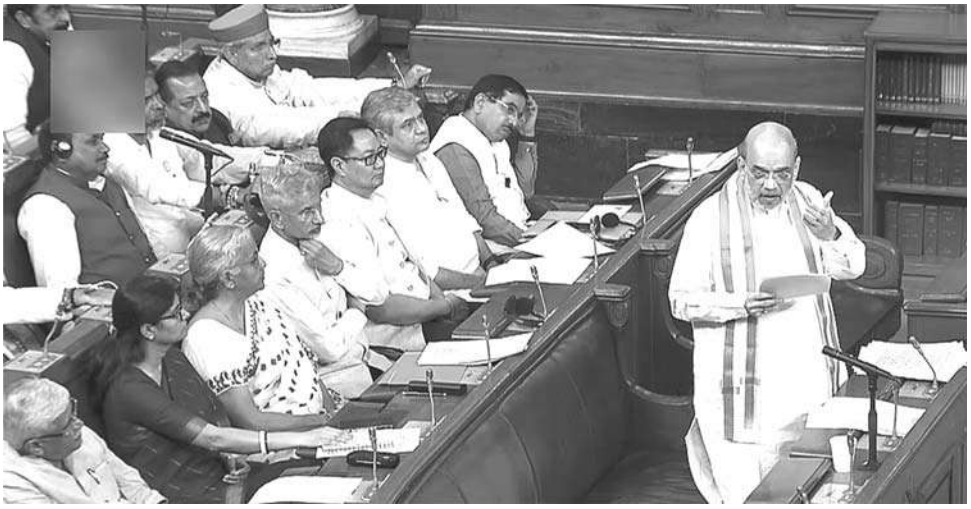

कानून के एंग्लो-सैक्सन दर्शन में कोई आकर्षण नहीं है। ऐसा नहीं है कि न्याय का यह आदर्शवादी सिद्धांत भारतीय संस्कृति से अलग है। बात सिर्फ इतनी है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जैसे कट्टर दक्षिणपंथी राष्ट्रवादियों और उनके प्रशंसकों को इसकी जानकारी नहीं है। तमिल महाकाव्य सिलप्पादिकारम की नायिका कन्नगी का ज्वलंत उदाहरण है, जो मदुरै को जला दिए जाने का श्राप देती है क्योंकि राजा ने एक निर्दोष व्यक्ति को मार डाला था और वह निर्दोष व्यक्ति उसका पति था। कई राष्ट्रवादी भारतीयों के दिमाग में उपनिवेशवाद से मुक्ति के उत्साह के कारण वह नैतिक कल्पना नहीं है जो सिलप्पदिकारम के लेखक इलंगो के पास थी। इसी तरह, कई भारतीयों, विशेषकर शिक्षित बहुसंख्यकों के लिए, संविधान की प्रस्तावना में निहित मौलिक सिद्धांत और अध्याय III के मौलिक अधिकार घृणित चीजें हैं क्योंकि वे एक सुरक्षित समाज चाहते हैं, भले ही इसका मतलब बुनियादी स्वतंत्रता के बिना ही क्यों न हो। यह शिक्षित भारतीयों के लिए अनूठा नहीं है। यह दुनिया भर में कई मध्यमवर्गीय लोगों की इच्छा है। यही कारण है कि कई भारतीय और अन्य लोग सिंगापुर की सुरक्षा के स्वर्ग के रूप में प्रशंसा करते हैं, और शहर-राज्य में बुनियादी स्वतंत्रता की अनुपस्थिति उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। शाह तब कुतर्क करते नजर आए जब उन्होंने दावा किया कि नए कानून से राजद्रोह को अपराध के रूप में हटा दिया गया है क्योंकि इसका इस्तेमाल अंग्रेजों ने बाल गंगाधर तिलक, एम.के. गांधी और वल्लभभाई पटेल जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करने के लिए किया था - बेशक, वे जवाहरलाल नेहरू का उल्लेख नहीं करेंगे जिन्होंने ब्रिटिश काल की जेलों में सबसे लंबा समय बिताया था क्योंकि उनकी पार्टी और उसके संरक्षक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, नेहरू के प्रति गहरी नफरत रखते हैं - लेकिन नए कानून के तहत देश के खिलाफ बोलने वालों को सजा दी जाएगी, हालांकि सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं होगी क्योंकि यह अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा है।

शाह, राजद्रोह को एक नए कानून के तहत वापस ले आए हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश में देशद्रोह तभी होता है जब लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हिंसक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, और इसका मतलब यह नहीं है कि आप देश के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। यदि कोई नागरिक कहता है कि भारत एक गंदा देश है, कि भारतीय लोग जातिवादी और सांप्रदायिक हैं, कि भारत का अतीत कई मायनों में अनुचित और अन्यायपूर्ण और अलोकतांत्रिक था, तो वह देशद्रोह नहीं कर रहा है। ये ऐसे तर्क हैं जो एक आजाद देश में दिए जा सकते हैं और दिए जाने चाहिए। नया कानून इसके खिलाफ है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि एक दक्षिणपंथी भाजपा सरकार, अपने संकीर्ण राष्ट्रवाद के दर्शन के साथ, इन कानूनों को ला रही है। जो देश आत्म-आलोचना करने से इनकार करता है वह बर्बाद हो जाता है। भारत एक पिछड़ा देश बन गया क्योंकि इसमें आत्म-आलोचना की भावना नहीं बची है। हलवे का टेस्ट खाने में ही है। इसलिए, इन नए कानूनों के गुण या दोष जो भी हों, यह इस पर निर्भर करेगा कि कानून और व्यवस्था मशीनरी उनका उपयोग कैसे करती है और अदालतें उनकी व्याख्या कैसे करती हैं। एक औपनिवेशिक पुलिस संरचना जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को डराने-धमकाने के लिए लाठी चलाना है, सर्वोत्तम कानूनों को कमजोर कर सकती है। एक अच्छा कानून अपने आप में इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इसे न्यायपूर्वक लागू किया जाएगा। जातिवादी और सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों से ग्रस्त पुलिस बल केवल असहाय लोगों पर क्रूरता कर सकता है। जो न्यायाधीश अपने राजनीतिक आकाओं पर नजर रखते हैं, वे कभी भी सड़क पर अन्याय करने वाले पुरुष या महिला की सुरक्षा के प्रति खड़े नहीं होंगे। शक्तिशाली भारत के बारे में मोदी की संकीर्ण सोच बहुत ही भोली-भाली है, और यही भोलापन शाह द्वारा कानूनों के लिए किए गए दावों के पीछे छिपा है। ये नए कानून संदिग्ध हैं क्योंकि ये सत्तावादी रवैये वाली सरकार के जरिए आए हैं, जो मुसोलिनी की फासीवादी विचारधारा में विश्वास करती है: 'राज्य में सब कुछ, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं, राज्य के खिलाफ कुछ भी नहीं।'

Nitish Kumar elected as new JDU President after Lalan Singh quits

Bihar Chief Minister Nitish Kumar was unanimously elected as President of the Janata Dal (United) at the party's National Executive meeting held in New Delhi on Friday.Kumar was appointed as the JD(U) Chief after Rajiv Ranjan Singh alias Lalan Singh stepped down from the post during the party meeting which began at the Constitution Club of India here. Taking the media, Party leader Shravan Kumar said that Lalan Singh proposed the name of Nitish Kumar in the meeting, which was accepted by the party leaders unanimously.However, the party leaders said that the final announcement will be made in the evening after the National Council Meeting.

JD(U) state president Umesh Kushwaha said that the party's national executive requested Bihar chief minister Nitish Kumar to take over the charge in the larger interest of the party and nation.The change in the JDU's top leadership also comes months before the 2024 Lok Sabha election and speculation over Nitish Kumar having Prime Ministerial ambition. The party will hold the national council meeting later in the day, which will take another decision at party level.Meanwhile, BJP took a dig at the meeting saying nothing will change in JD(U) if Nitish Kumar again becomes the party president.

BJP leader from Bihar Shahnawaz Hussain said, "The saffron party has a strong presence in Bihar and it will emerge as a strong party in the Lok Sabha election next year and state assembly election scheduled to be held in 2025.

यौन शोषण के खिलाफ

कैंपस से लेकर सड़क और संसद भवन में गूंजी आवाज

● **सोनिया यादव**

महिला सुरक्षा का मुद्दा इस देश में तभी सुर्खियों में आता है, जब या तो कहीं चुनाव हों, या कहीं कोई बड़ी घटना घटित हो गई हो। इसके अलावा ये मुद्दा हमारी सरकारी नीतियों में भी सिर्फ दावों और वादों के बीच पीठ थपथपाने के लिए इस्तेमाल होता रहा है। हालांकि छात्र और महिला संगठन तमाम आंदोलनों- प्रदर्शनों के जरिए साल भर सरकार को इस गंभीर विषय पर नींद से जगाने की कोशिश करते रहे हैं। न्यूजक्लिक के इस लेख में एक नजर 2023 के उन विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों पर जो विश्वविद्यालय कैंपस से लेकर सड़कों और संसद भवन तक महिला हिंसा और यौन शोषण के खिलाफ हुए।

☞ **महिला पहलवानों का बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन** :- इस साल की शुरुआत में भारतीय कुश्ती महासंघ 18 जनवरी को उस वक्त अचानक खबरों में आ गया, जब देश के जाने माने दिग्गज पहलवान फेडरेशन

के खिलाफ राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना देने बैठ गए। इन पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह पर कुश्ती संघ को मनमाने तरीके से चलाने का आरोप लगाया। धरने पर बैठी महिला पहलवानों ने महासंघ के प्रेसिडेंट पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप भी लगाए। इन पहलवानों में ओलंपिक्स, एशियन गेम्स और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को कई पदक दिलाने वाली महिला कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया समेत देश के कई दिग्गज पहलवान शामिल थे। खेल मंत्री से कई दौर की बातचीत के बात लगभग तीन दिन बाद ये प्रदर्शन जांच के आश्वासन के बाद खत्म हो गया। हालांकि तीन महीने बाद किसी ठोस कार्रवाही के आभाव में ये खिलाड़ी एक बार फिर पोडियम से फुटपाथ पर धरना देने के लिए लौटे। इस बार ये धरना कई महीने चला। खिलाड़ियों के समर्थन में आम लोग और महिला संगठन भी आए। कई नेताओं का भी जंतर-मंतर पर जमावड़ा हुआ। नई संसद के उद्घाटन के दिन खिलाड़ियों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला और इसके बाद इनका धरना समाप्त हो गया। फिलहाल ये मामला

अदालत में है और पहलवान न्याय का इंतजार कर रहे हैं।

☞ **अंकिता भंडारी के न्याय के लिए उठे हाथ :-** उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में महिला और मानवाधिकार संगठनों की संयुक्त फैक्ट फाइंडिंग टीम ने 7 फरवरी को दिल्ली के प्रेस क्लब में अपनी फैक्ट रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में कई चिंताओं और सवालों के साथ ही उन तथ्यों को भी सामने रखा गया, जो टीम ने अंकिता के घर से लेकर घटनास्थल तक अपनी आंखों से देखा और लोगों से सुना था। इसके अलावा एसआईटी जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट के भी तमाम पहलुओं को भी इस रिपोर्ट के केंद्र में रखा गया था। इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में एसआईटी पर जांच में जानबूझकर लापरवाही बरतने समेत वनंतरा रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने, पुलिस रिमांड की मांग न करने और राजस्व पुलिस से लेकर उत्तराखंड पुलिस तक के गोलमोल भूमिका पर सवाल खड़े किए गए थे। देश में दिन-प्रतिदिन महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा और आरोपियों को मिलते सरकारी संरक्षण के खिलाफ 14 फरवरी को भी दिल्ली के जंतर-मंतर पर ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन के नेतृत्व में तमाम महिला कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में अंकिता की मां सोनी देवी भी शामिल हुई थीं

और उन्होंने शासन-प्रशासन पर जानबूझकर मामले की गंभीरता को दबाने का आरोप लगाया था। इस प्रदर्शन में महिलाओं ने एक सुर में सरकार से महिलाओं की सुरक्षा के वादे नहीं नीयत और नीति की मांग की थी।

☞ **जूनियर महिला कोच का मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ संघर्ष :-** अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हरियाणा में एक राज्यस्तरीय कार्यक्रम के दौरान जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर महिलाओं के सम्मान में कसीदे पढ़ रहे थे, ठीक उसी समय महिला संगठन उनके मंत्री संदीप सिंह को लेकर जोरदार प्रदर्शन कर रहे थे। यहां महिला प्रदर्शनकारियों से पुलिस के दुर्व्यवहार के आरोप भी लगे। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति (एडवा) समेत कई अन्य नागरिक और महिला संगठनों की न्यायिक संघर्ष समिति ने एक साझा बयान में कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री महिलाओं की जायज मांगों को अनसुना करके अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का ढोंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को महिला विरोधी रवैये के लिए सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। ध्यान रहे कि भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और हरियाणा में बीजेपी के नेता संदीप सिंह के खिलाफ एक जूनियर महिला कोच ने बीते साल 26 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को संदीप सिंह के खिलाफ चंडीगढ़ के सेक्टर 26 पुलिस थाने में केस भी दर्ज हुआ था। तब से इस मामले को लेकर हरियाणा की सड़कों और विधानसभा भवन में कई प्रदर्शन भी हुए, बावजूद इसके बीजेपी मंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये मामला भी फिलहाल कोर्ट में है और पीड़िता न्याय की आस लगाए बैठी है। मणिपुर में महिलाओं के साथ हिंसा, एकजुट हुआ देश इस साल की सबसे बड़ी महिला हिंसा की खबर मणिपुर से आई, जहां कुछ महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड कराने और

गैंगरेप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद देशभर में प्रगतिशील नागरिक समाज के लोगों में भारी रोष देखने को मिला। इसको लेकर देश के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन हुए। दिल्ली से लेकर यूपी-बिहार और हरियाणा में जगह-जगह प्रदर्शन किए गए। ये प्रदर्शन किसी एक संगठन या दल का नहीं था बल्कि आम जनता का था, जिसने हिंसा को नकारने का आह्वान किया था। इसमें बड़ी संख्या में छात्र, नौजवान और महिला संगठन और नागरिक समाज के लोग शामिल हुए थे।

मानसून सत्र के दौरान संसद में भी इस मामले ने खूब तूल पकड़ा और सदन में विपक्षी सांसदों ने नारे लगाए, तख्तियां दिखाईं। सांसद इस मुद्दे पर चर्चा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूरे मामले पर बयान की मांग कर रहे थे। कई दिन संसद में ये हंगामा जारी रहा, सांसद निलंबित हुए और विपक्ष ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने एकजुट होकर 'इंडिया फॉर मणिपुर' की तख्तियां लिए विरोध प्रदर्शन किया।

☞ **हैदराबाद इफ्लू विश्वविद्यालय में यौन उत्पीड़न के खिलाफ लांबद हुए छात्र :-** इसी साल अक्तूबर में हैदराबाद के अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय (ईएफएलयू) परिसर में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कथित तौर पर एक छात्रा का यौन उत्पीड़न किए जाने को लेकर छात्रों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में पीड़िता के लिए न्याय की मांग के साथ ही कैंपस में सुरक्षा का मुद्दा भी उठा। इफलू के विद्यार्थी काफी समय से विश्वविद्यालय में यौन उत्पीड़न की संवेदनशीलता, रोकथाम और निवारण (स्पर्श) समिति के पुनर्गठन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे जिसमें अधिकतर तादाद में महिला छात्राएं मौजूद थीं।

☞ **यौन शोषण के खिलाफ बनारस हिंदू यूनीवर्सीटी के छात्रों का धरना :-**

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू एक बार फिर यौन शोषण को लेकर इस साल सुर्खियों में रहा। पिछले साल नवंबर में आईआईटी बीएचयू के परिसर में अध्ययनरत एक बीटेक छात्रा के साथ परिसर में हुए यौन उत्पीड़न का मामला सामने आने के बाद हजारों विद्यार्थी धरने पर बैठ गए। विद्यार्थियों ने आरोपियों के जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए शांतिपूर्ण धरना किया। कैंपस में पोस्टर हाथ में लिए विद्यार्थियों ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम को बढ़ाने और GSCASH को लागू करने की मांग रखी। बता दें कि बीएचयू में 2017 में हुए लड़कियों के ऐतिहासिक आंदोलन की सबसे बड़ी मांग विश्वविद्यालय में जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट (GSCASH) को लागू करना था। इसके बाद भी यौन शोषण को लेकर हुए कई बड़े प्रदर्शनों में छात्रों ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम के साथ ही GSCASH की मांग रखी लेकिन प्रशासन ने आज भी करीब पांच साल बीत जाने के बाद भी इस पर कोई सुनवाई नहीं की। इसके उलट लड़कियों पर हॉस्टल में तमाम पाबंदियां लगाने की कोशिश की गई। छात्रों को प्रदर्शन में भाग न लेने का नोटिस निकाल दिया गया और बात-बात पर लड़कियों को कैंपस के अंदर ही 'कैरेक्टर-सर्टिफिकेट' बांटे जाने लगे। जिसके खिलाफ छात्र खुलकर सामने आए। (साभार)

महिला पहलवान विनेश फोगाट ने लौटाया खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड

विश्व चौम्पियनशिप की पदक विजेता विनेश फोगाट ने मंगलवार को अपना खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार प्रधानमंत्री को लौटाने का फैसला किया और कहा कि जब पहलवान न्याय पाने के लिए बुरी तरह संघर्ष कर रहे हैं तब इस तरह के सम्मान निरर्थक बन गए हैं। इस पहलवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र में यह घोषणा की। उन्होंने पत्र को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी सरकार के उन फैंसी विज्ञापनों जैसी नहीं है जिनमें महिला सशक्तिकरण और उनके उत्थान की बात की जाती है। विनेश ने अपने पत्र में कहा है, ''मुझे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार दिया गया था जिनका अब मेरी जिंदगी में कोई मतलब नहीं रह गया है। हर महिला सम्मान से जीना चाहती है। इसलिए प्रधानमंत्री सर, मैं अपना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार आपको वापस करना चाहती हूँ ताकि सम्मान से जीने की राह में ये पुरस्कार हमारे ऊपर बोझ न बन सकें।'' विनेश को 2020 में भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। इससे पहले उन्हें 2016 में अर्जुन पुरस्कार मिला था।विनेश से पहले ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया और डेफलंपिक्स के चौंपियन वीरेंदर सिंह यादव ने अपने पद्मश्री पुरस्कार लौटा दिए थे। गुरुवार को संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) का अध्यक्ष चुना गया था। बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय के गुट ने इन चुनाव में 15 में से 13 पद जीते थे। पहलवानों ने इससे पहले मांग की थी कि बृज भूषण का कोई भी करीबी डब्ल्यूएफआई प्रशासन में नहीं होना चाहिए। चुनाव के बाद रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की थी। विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने बृजभूषण पर कई महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। उन्होंने इस साल के शुरू में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन भी किया था। यह मामला अब दिल्ली की अदालत में लंबित है। खेल मंत्रालय ने फैसला करते समय अपने संविधान के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर नव निर्वाचित पैनल को निलंबित कर दिया था और भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) को कुश्ती के संचालन के लिए एक तदर्थ पैनल का गठन करने के लिए कहा था। इस बीच खेल मंत्रालय ने कहा कि वह अपनी तरफ से काफी प्रयास कर चुका है और फिर से अपना फैसला बदलने के लिए उन्हें मनाने की कोशिश करेगा। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, ''हमने इस मामले में संज्ञान लेते हुए पहले ही डब्ल्यूएफआई की नवनिर्वाचित संस्था को निलंबित कर दिया। हमने अपने संविधान के प्रावधानों का पालन नहीं करने के लिए नई संस्था को निलंबित किया।'' उन्होंने कहा, ''पुरस्कार लौटाना उनके विरोध का तरीका है। लेकिन हम पहले ही भारतीय ओलंपिक संघ को तदर्थ समिति गठित करने के लिए कह चुके हैं जो नए चुनाव होने तक डब्ल्यूएफआई का कामकाज देखेगी। हम पहलवानों को समझाने की कोशिश करेंगे और उनसे पुरस्कार वापस लेने का आग्रह करेंगे।'' फोगाट ने कहा कि जब उन्हें सरकार के संदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए चुना गया तो वह बेहद खुश थी लेकिन मौजूदा स्थिति से वह निराश हैं। उन्होंने कहा,''मुझे साल याद है 2016 जब साक्षी मलिक ओलंपिक में पदक जीतकर आई थी तो आपकी सरकार ने उन्हें 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' की ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। जब इसकी घोषणा हुई तो देश की हम सारी महिला खिलाड़ी खुश थीं और एक दूसरे को बधाई के संदेश भेज रही थीं।'' विनेश ने कहा,'' आज जब साक्षी को कुश्ती छोड़नी पड़ी तब से मुझे वह साल 2016 बार बार याद आ रहा है। क्या हम महिला खिलाड़ी सरकार के विज्ञापनों पर छपने के लिए ही बनी हैं। हमें उन विज्ञापनों पर छपने में कोई एतराज नहीं है, क्योंकि उसमें लिखे नारे से ऐसा लगता है कि आपकी सरकार बेटियों के उत्थान के लिए गंभीर होकर काम करना चाहती है।'' उन्होंने कहा,''मैंने ओलंपिक में पदक जीतने का सपना देखा था, लेकिन अब यह सपना भी धुंधला पड़ता जा रहा है। बस यही दुआ करूँगी कि आने वाली महिला खिलाड़ियों का यह सपना जरूर पूरा हो। ''

जयशंकर ने खोला जस्टिन ट्रूडो का कच्चा चिट्ठा

कनाडा की पुलिस जल्द ही उन 2 लोगों को गिरफ्तार कर सकती है जिन पर खालिस्तानी समर्थक सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की जून में हत्या करने का संदेह है। बताया जा रहा है, वे दोनों अभी देश में ही हैं। एक मीडिया की खबर में यह जानकारी दी गई। ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में जून में निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 'द ग्लोब एंड मेल' अखबार के अनुसार पुलिस फिलहाल संदिग्धों पर नजर रखे हुए है और संभावना है कि कुछ ही हफ्तों में उन्हें पकड़ लिया जाएगा। अखबार ने 3 अज्ञात स्रोतों के हवाले से बताया कि निज्जर की हत्या के बाद 2 संदिग्ध हत्यारों ने कनाडा नहीं छोड़ा और पुलिस कई महीनों से उन पर नजर रखे हुए है।

गौरतलब है कि सितंबर में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 18 जून को सरे शहर के गुरुद्वारे के बाहर की गई खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की संभावित संलिप्तता का आरोप लगाया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। भारत ने 2020 में निज्जर को 'आतंकवादी' घोषित किया था। भारत ने ट्रूडो के आरोपों को बेतुका बताकर खारिज कर दिया था। अब खबर में कहा गया कि औपचारिक आरोप-पत्र दायर करने के बाद पुलिस हत्यारों की कथित संलिप्तता और भारत सरकार से उनके संबंध के बारे में खुलासा करेगी। 'ग्लोबल न्यूज' ने 'बीसी गुरुद्वारा काउंसिल' के प्रवक्ता मोनिंदर सिंह के हवाले से कहा कि, जैसा कि कहा जा रहा है कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है, इससे समुदाय के लोग राहत की सांस लेंगे। खबर के अनुसार जांच दल ने कहा कि वह निज्जर की हत्या के मामले में गिरफ्तारी को लेकर मीडिया में आ रहीं खबरों से अवगत है, लेकिन वह अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा, क्योंकि जांच जारी है। खबर में यह भी कहा गया कि कनाडा के आरोपों के बाद नवंबर में अमेरिका ने अपने आरोपों में भी एक कनाडाई-अमेरिकी सिख नागरिक की हत्या की साजिश को रेखांकित किया था। अमेरिकी संघीय अभियोजकों ने नवंबर में आरोप लगाया था कि निखिल गुप्ता नाम का व्यक्ति, एक खालिस्तानी समर्थक की हत्या की साजिश रचने के लिए एक भारतीय कर्मचारी के साथ काम कर रहा था। हालांकि खालिस्तानी समर्थक अलगाववादी सिख नेता का नाम नहीं बताया गया, लेकिन मीडिया की खबरों में उसकी पहचान भारत में प्रतिबंधित संगठन 'सिख फॉर जस्टिस' के नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू के रूप में की गई है। अमेरिकी अभियोजकों के आरोपों की जांच के लिए भारत पहले ही एक जांच समिति गठित कर चुका है। विदेश मंत्री

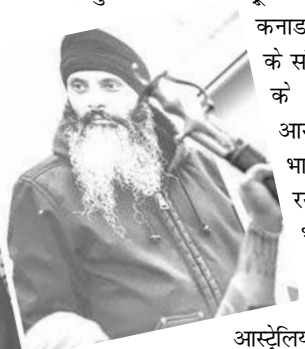

एस जयशंकर ने इस महीने की शुरुआत में राज्यसभा में कहा था कि कनाडा ने भारत के साथ कोई विशेष सबूत या जानकारी साझा नहीं की है। सितंबर में ट्रूडो के आरोपों के कुछ दिनों बाद, भारत ने कनाडाई नागरिकों को वीजा जारी करना अस्थाई रूप से निलंबित कर दिया और ओटावा से समानता सुनिश्चित करने के लिए देश में अपनी राजनयिक उपस्थिति को कम करने के लिए कहा था। भारत ने वीजा सेवाएं निलंबित होने के एक महीने से अधिक समय बाद पिछले महीने कनाडा में कुछ वीजा सेवाओं को फिर से शुरू किया। वही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिख चरमंपथी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और भारतीय एजेंटों के बीच संभावित संबंध के कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों के बाद कनाडा के साथ भारत के संबंधों में आए तनाव के सिलसिले में आस्ट्रेलिया के सामने भारतीय परिप्रेक्ष्य को रखा। जयशंकर ने भारत-ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्रियों के बीच वार्ता के दौरान आस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेन्नी वोंग को भारत और कनाडा के बीच के मुद्दों के बारे में बताया। जयशंकर ने वोंग के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमारे नजरिए से वास्तव में अहम मुद्दा वह छूट है जो कनाडा में चरमपंथ और कट्टरपंथ को दी जा रही है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया का भारत एवं कनाडा के साथ अच्छा एवं मजबूत संबंध है। उन्होंने कहा कि इसलिए जरूरी है कि ऑस्ट्रेलिया को इस मुद्दे पर हमारा परिप्रेक्ष्य पता चले। ब्रिटिश कोलंबिया में 18 जून को हुई खालिस्तानी अलगाववादी निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की 'संभावित' संलिप्तता का ट्रूडो द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद भारत एवं कनाडा के बीच संबंधों में बड़ा तनाव आ गया है। भारत ने 2020 में निज्जर को आतंकवादी घोषित किया था। भारत ने ट्रूडू के आरोप को 'बकवास' एवं 'राजनीति से प्रेरित' करार देकर खारिज कर दिया। कनाडाई संसद में ट्रूडो द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद से भारत एवं कनाडा ने एक दूसरे के एक-एक वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित कर दिया। भारत ने यहां कनाडाई मिशनों में राजनयिक उपस्थिति में 'समता' पर जोर डाला , फलस्वरूप 41 राजनयिक कनाडा वापस बुला लिए गए। भारत ने कहा है कि कनाडा ने ट्रूडो के दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया है। जयशंकर ने ब्रिटेन में कहा था कि यदि आपके पास ऐसे आरोप लगाने की वजह है तो कृपया, हमारे साथ सबूत साझा कीजिए। हम जांच से इनकार नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी (सबूत) मिलने का इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें संभवत: देना है। उन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है।

War rocks Middle East amid the 'era of peace' in year 2023

Before the October 7 attacks, one could have thought that many leaders of the Arab world had forgotten about the Palestinians.Political calculations, above all the two-state-solution with an independent Palestinian state, seemed to be of little concern anymore. The priorities had apparently shifted away from the Palestinians and, remarkably, towards Israel.In 2020, the United Arab Emirates (UAE), Bahrain, Morocco and Sudan signed normalization agreements with Israel.

Also, talks with Saudi Arabia seemed to put Israel well on the way to peace with the influential neighbor in its south. According to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, all of this heralded an "era of peace." But then came the October 7 attack by the militant organization Hamas, which is classified as a terrorist organization in Germany, the EU, the US and several others. Hamas fighters killed around 1,100 Israeli citizens and kidnapped around 250 people. Around half have been released since, in exchange for Palestinian prisoners from Israeli jails. In turn, Israel launched air strikes on the Gaza Strip, and a ground offensive began at the end of October. Israel accuses Hamas of installing its military infrastructure in areas inhabited or used by civilians. The Hamas-run Health Ministry has since put the number of deaths in the Gaza Strip at more than 21,000.Meanwhile, many Arab states have expressed their solidarity with Palestinians in the Gaza Strip.

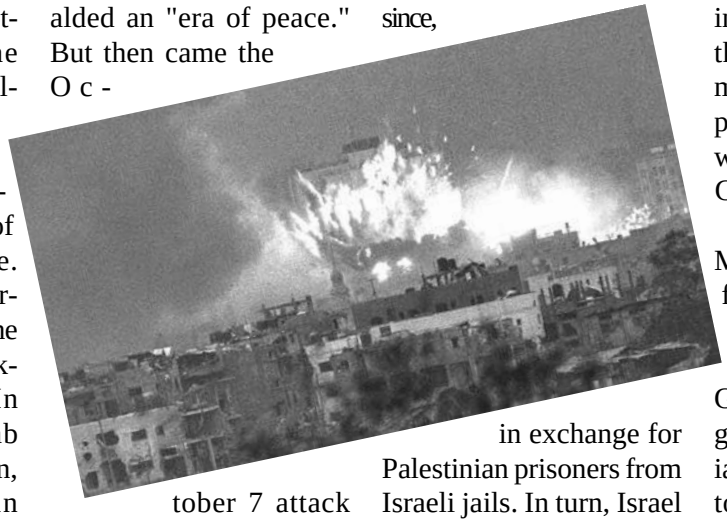

Jordanian Foreign Minister Ayman Safadi, for example, said that the war that Israel is waging against Hamas in the Gaza Strip is a "blatant aggression" against Palestinian civilians and threatens to destabilize the entire Middle East. By blocking the supply of food, medicine and fuel, he said, Israel was committing "war crimes."

☞ **Palestinians are back on the agenda :-** As of now, the Hamas terror attack has at least achieved one thing: The Palestinians and their concerns have returned to regional and international agendas. As a result, the Middle East conflict, which has remained unresolved for more than 70 years, is now back in the spotlight. "Arab states are driven by their own stability concerns," Andre Bank, Middle East researcher at the Hamburg-based think tank, the Institute for Global and Area Studies (GIGA), told DW. Israel's direct neighbors Jordan and Egypt both signed peace treaties with Israel decades ago. They now fear, however, that a further escalation in Gaza or the West Bank might lead to a major displacement of Palestinians which could then lead to unrest in their own countries. "As a result, demonstrations are allowed in Egypt, but not on Cairo's Tahrir Square, which was the center of the democracy movement in 2011," Bank said, adding that "President Abdel Fattah el-Sissi is worried that such protests could turn into demonstrations of solidarity in the spirit of the Arab Spring." In Jordan, pro-Palestinian protests are allowed, however, not near the border with the West Bank. "The concern is that protests there could easily get out of control," Bank said.

☞ **Role of the Gulf states :-** In the Gulf states, though, protests have hardly happened so far. This is consistent with the Emirates' positioning, Bank told DW. The UAE even sided with Israel, at least initially, he added. The small state of Qatar — some of the Hamas leadership live in Qatar's capital Doha — publicly criticized Israel several times. However, in an interview with the German newspaper Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) at the end of November, Qatar's head of government, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, described his country's relationship with Israel as "pragmatic." "We in Qatar have repeatedly said that the problems are the occupation and the Palestinian issue, there is no other problem than that." If a solution to these issues is not found, the region would forever be trapped in a cycle of violence, Al Thani said, adding "otherwise, why should we have a problem with Israel if this is seriously addressed?"

☞ **Common interests :-** Experts doubt that the rapprochement between Israel and the Arab world will remain deadlocked in the future. Johannes Becke, professor of Israel and Middle East Studies at the Heidelberg Center for Jewish Studies, told DW that "harsh rhetoric was expressed at the summit of Arab-Muslim states in Riyadh at the beginning of November, but it also stopped right there."

The main reasons for this, he says, are economic and geostrategic interests of Arab states with regard to Israel that remain largely untouched by the conflict in Gaza. Israel is generally regarded as highly attractive partner for business and technology. Rapprochement with Israel also brings advantages in relations with the United States and other Western countries. Furthermore, Israel is an important geostrategic partner for those countries that — like the Gulf states — also want to see Iran's influence in the region limited.

☞ **Intercepted missiles :-** "Saudi Arabia improved its relations with Iran in 2023," Becke said. However, the rapprochement between Saudi Arabia and Israel, which until the Hamas attack ap-

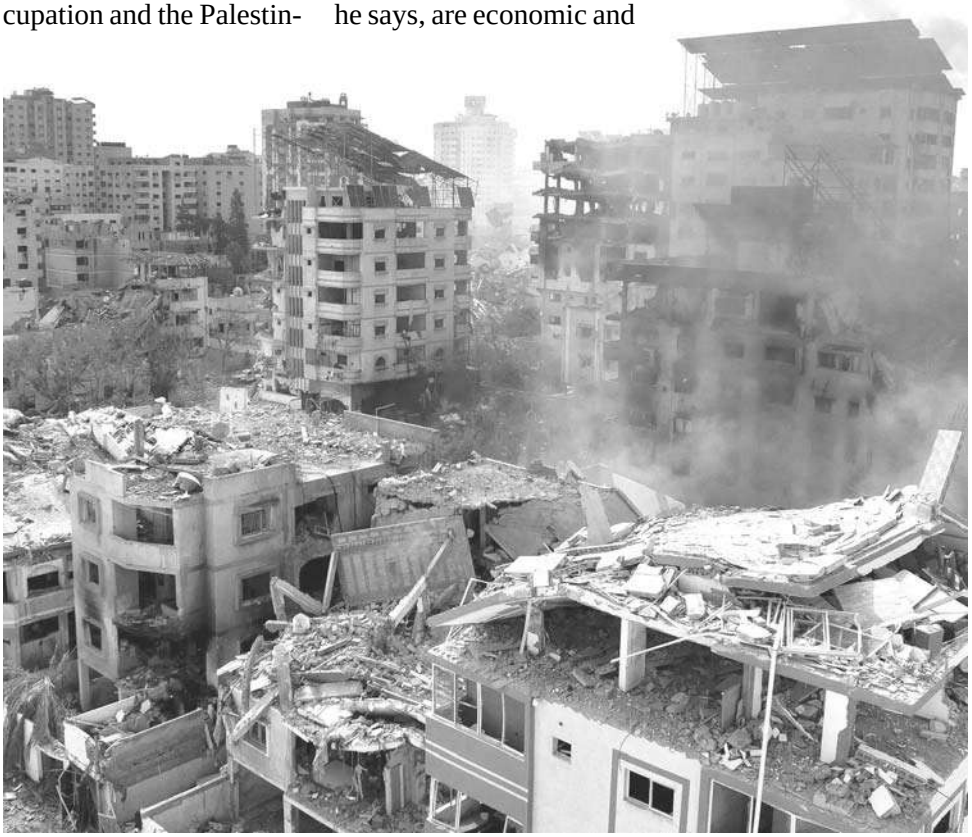

peared to be rapid, seems to be on hold for the time being due to the war in Gaza. However, when Iran-backed Houthi rebels in Yemen started firing missiles towards Israel in early December to support Hamas in its fight against Israel, Saudi Arabia took action and intercepted the missiles aimed at Israel. "Until recently, these missiles were fired towards Saudi Arabia itself and may also be aimed at the kingdom again," Becke said, adding that "in this sense, the geopolitical arguments in favor of an Arab-Israeli rapprochement remain unchanged, rather on the contrary, the Hamas attack may even have strengthened them."

☞ **Potential for mobilization :-** Still, the ongoing pro-Palestinian rallies in the Arab and Islamic world demonstrate the war's mobilization potential. This is precisely why Arab governments are likely to be interested in ending it as quickly and as permanently as possible before the protests jeopardize their own stability. However, rapprochement with Israel may only be resumed after the war, and once the Palestinians benefit from of a new version of the two-state solution. In the FAZ interview, Qatar's head of government Al-Thani already outlined the framework for this: "The Palestinian issue can no longer be swept under the carpet," he said.

कौन हैं असम के सिंघम आनंद मिश्रा? बिहार में बीजेपी के टिकट पर लड़ सकते हैं चुनाव

असम-मेघालय कैडर 2011 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी और लखीमपुर (असम) एसपी आनंद मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। मिश्रा काफी लोकप्रिय पुलिस अधिकारी रहे हैं और सोशल मीडिया में वे 'सिंघम' के नाम से मशहूर हैं। माना जा रहा है कि राजनीति के मैदान में उतरने के लिए मिश्रा ने इस्तीफा दिया है। आनंद मिश्रा ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि 16 जनवरी, 2024 से मैं पदमुक्त होना चाहता हूं। आनंद ऐसे व्यक्ति हैं जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के प्रति अपने समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं।

☞ **बक्सर सीट से लड़ना चाहते हैं चुनाव :-** माना जा रहा है कि आनंद मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। उनके बारे में कहा जा रहा है कि वे राज्य की बक्सर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं।

☞ **मोहन भागवत से की थी मुलाकात :-** आनंद ने कुछ समय पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत से भी मुलाकात की थी। इसी आधार पर अटकलें हैं कि वे जल्द ही भाजपा जॉइन कर सकते हैं। भाजपा के कई अन्य नेताओं से भी उनके अच्छे संबंध हैं। मिश्रा ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि निजी जीवन में स्वतंत्रता और सामाजिक सरोकारों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। मिश्रा बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड अंतर्गत पड़सौरा गांव के निवासी हैं। उनकी शिक्षा और परवरिश कोलकाता में हुई है। असम के नगांव जिले में तैनाती के दौरान ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए वे काफी चर्चा में रहे थे।

हिजाब से हटेगा बैन

राजनीति के चलते जरूरत से ज्यादा बढ़ा विवाद?

● **सोनिया यादव**

हम हिजाब सर्कुलर को वापस ले लेंगे। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कपड़ों का चयन करना व्यक्ति का अपना विशेषाधिकार है।ष ये बयान कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार, 22 दिसंबर को मैसुरू के एक कार्यक्रम में हिजाब से प्रतिबंध हटाने का ऐलान करते हुए दिया। उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक ने स्कूल-कॉलेजों में लड़कियों के हिजाब पहनने पर लगे बैन को हटाने का फैसला किया है। और इसके लिए अधिकारियों को 2022 में पिछली बीजेपी सरकार द्वारा लाए गए हिजाब पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश को वापस लेने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री के इस भाषण के साथ ही कर्नाटक की सियासत एक बार फिर हिजाब को लेकर गर्मा गई है। विपक्षी दल बीजेपी इसके विरोध में उतर आई है, तो वहीं सत्ता पक्ष कांग्रेस इसे अपनी पसंद और अधिकार की बात से जोड़ रही है। बता दें कि बीते साल 2022 में कर्नाटक का हिजाब मामला उस वक्त पूरे देश के लिए सुर्खियां बन गया था, जब प्रदेश की पिछली बीजेपी सरकार ने हिजाब प्रतिबंधित करने का आदेश दिया था। तब ये मुद्दा शिक्षा और धर्म से आगे बढ़ता राजनीति और कानूनी लड़ाई के बीच उलझ कर लड़कियों को शिक्षा से दूर करने की एक और साजिश के तौर पर देखा जाने लगा था। हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ये मामला फिलहाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट के खंडित फैसले के लगभग एक साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी सर्वोच्च अदालत में इसके लिए बड़ी बेंच गठन होना बाकी है।

☞ **हिजाब को लेकर कांग्रेस और बीजेपी का पक्ष और राजनीति** :- 'द हिंदू' की खबर के मुताबिक कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने ये संकेत दिया था कि

सत्ता में आने पर वो हिजाब बैन को खत्म कर देगी। हालांकि मैसुरू कार्यक्रम में पहली बार मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इसका सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया है। सभा को संबोधित करते हुए सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि पीएम मोदी का 'सब का साथ, सबका विकास' झूठा है। बीजेपी लोगों और समाज को कपड़े, पहनावे और जाति के आधार पर बांट रही है। उन्होंने आगे कहा, ष्मैं तुम्हें क्यों परेशान करूं? आप जो भी ड्रेस पहनना चाहें पहन लें। तुम जो चाहो खाओ। अपनी पसंद का खाना खाना आपका अधिकार है। मैं जो भी खाऊंगा वो मेरा अधिकार है। मैं धोती पहनता हूं। कोई शर्ट-पैंट पहन सकता है। इसमें गलत क्या है। राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह के मामलों का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए।' उधर, बीजेपी ने भी इस पूरे मामले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि वह हिजाब प्रतिबंध को रद्द करने के किसी भी कदम का विरोध करेगी। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के ऐलान का विरोध करते हुए पार्टी ने लिखा, 'मुख्यमंत्री शांतिपूर्ण समाज में धर्मांधता का जहर घोलने जा रहे हैं।' पार्टी के मुताबिक सिद्धारमैया वोट बैंक की राजनीति के लिए इस तरह का फैसला ले रहे हैं। यूनिफॉर्म छात्र-छात्राओं में समानता सुनिश्चित करती है। लेकिन मुख्यमंत्री लोगों को बांटने की कोशिश कर रह रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जनता उन्हें सबक सीखा देगी।

साल 2021 में शुरू हुआ विवाद, अब तक राजनीति की भेंट चढ़ा।

ध्यान रहे कि इस पूरे विवाद की शुरुआत साल 2021 में हुई थी। जब उडुपी के सरकारी पीयू कॉलेज में छह लड़कियों को कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी गई थी। जिसके बाद छात्राओं ने हिजाब पहनकर कैंपस में घुसने की कोशिश की थी लेकिन उन्हें बाहर ही रोक दिया गया था।

इन लड़कियों ने इसके बाद कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया था और जनवरी 2022 में उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका दायर कर दी थी। ये मामला शुरू तो उडुपी जिले से हुआ था लेकिन जल्द ही जंगल की आग की तरह बाकी जिलों में भी फैल गया। शिवमोगा और बेलगावी जिलों में भी हिजाब पहनकर कॉलेज आने वाली मुसलमान छात्राओं पर रोक लगा दी गई। भगवा गमछा पहने छात्रों ने हिजाब पहने छात्राओं के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। कोंडापुर और चिकमंगलूर में प्रदर्शन और प्रदर्शनों के खिलाफ हिंदू और मुसलमान छात्रों के प्रदर्शन शुरू हो गए। इस दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें हिजाब पहने कॉलेज जा रही छात्रा मुस्कान खान के खिलाफ भगवा गमछा डाले युवा छात्रों की भीड़ नारेबाजी कर रही थी। ये घटना कर्नाटक के मंड्या जिले में हुई थी लेकिन जल्द ही हिजाब बनाम भगवा गमछे की लड़ाई पूरे कर्नाटक में शुरू हो गई। हालांकि कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब मामले पर सुनवाई शुरू होने के तीन दिन पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री बसावराज बोम्मई की सरकार ने एक आदेश जारी करके सभी छात्रों के लिए कॉलेज प्रशासन की तरफ से तय यूनिफॉर्म को पहनना अनिवार्य कर दिया। इस आदेश के दो दिनों के भीतर ही प्रदर्शन राज्य भर में फैल गए और कई जगह हिंसक घटनाएं भी हुईं।

8 फरवरी 2022 को उडुपी के एमजीएम कॉलेज में सैकड़ों छात्रों की भीड़ ने हिजाब पहने लड़कियों के खिलाफ जय श्री राम का नारा लगाया। कर्नाटक के कई इलाकों में हिंसक झड़पें हुईं। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस छोड़नी पड़ी। मुख्यमंत्री को एहतियात के तौर पर कई दिनों तक सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश देना पड़ा। इसके बाद मामला कर्नाटक हाई कोर्ट

की तीन जजों की बेंच में पहुंचा। जिसने सरकार के फैसले का समर्थन किया था।

☞ **हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट और प्रदेश से पूरे देश में चला विवाद** :-हाईकोर्ट के बाद, उडुपी की मुस्लिम छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। मुस्लिम छात्रा निबा नाज की ओर से विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि कर्नाटक शिक्षा अधिनियम छात्रों द्वारा पहनी जाने वाली किसी भी अनिवार्य वर्दी का प्रावधान नहीं करता है और हिजाब पहनने का अधिकार निजता के अधिकार के दायरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट जुलाई 2022 में हिजाब बैन को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के लिए राजी हो गया था। सितंबर, 2022 में करीब 10 दिनों की बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद 13 अक्टूबर को इस मुद्दे पर खंडित फैसला आया, जिसमें दो पीठासीन न्यायाधीश, जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया, एक समझौते पर नहीं आ सके। जहां एक ओर न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखा, वहीं न्यायमूर्ति धूलिया ने हिजाब पहनने को पसंद का मामला बताते हुए इसे अनुच्छेद 14, 15 और 19 से जोड़ा। उन्होंने अपने फैसले में लड़कियों की शिक्षा को सर्वोपरि माना। मौजूदा समय में ये मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को भेजा गया है और शीर्ष अदालत इस पर भी विचार करेगी कि क्या मामले को नौ न्यायाधीशों की पीठ को भेजा जाना चाहिए। कुल मिलाकर ये मामला अभी अदालत के ठंडे बस्ते में है।

☞ **हिजाब को लेकर चिंता और सवाल** :- गौरतलब है कि इस पूरे विवाद में कई लोग पक्ष और विपक्ष में बंटे हुए थे, तो वहीं एक धड़ा प्रगतिशील लोगों का भी था, जो हिजाब के हिमायती तो नहीं थे, लेकिन वो इसे जबरन उतरवाने के खिलाफ थे। और इसका सबसे बड़ा कारण उनका ये डर था कि कहीं इसके चलते मुस्लिम लड़कियां शिक्षा से दूर न हो जाएं और शायद यही वजह रही कि इसके विरोध में और ज्यादा महिलाओं ने न चाहते हुए भी हिजाब की ओर कदम बढ़ा दिए। यहां ये भी गौर करने वाली बात थी कि अचानक, अकादमिक सत्र के बीच हिजाब का मुद्दा पैदा कैसे हुआ? जिसे बेवजह और जरूरत से ज्यादा हवा दी गई। कोर्ट ने ये भी कहा कि जिस तरह सामाजिक अशांति और द्वेष फैलाने की कोशिश की गई वो सबके सामने है। उसमें अब बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इस तमाम बहस में ये बड़ा सवाल है कि क्या हिजाब पहनना आजादी का संकेत है या भारतीय मुसलमान की पहचान को जाहिर करने का तरीका। हिजाब उतारना धार्मिक और राजनीतिक मामला है या सत्ता और पितृसत्ता का हथियार।

(साभार)

नए रूप में लौट आया है कोरोना

● रवि शंकर दुबे

भारत में साल 2020 से लेकर 2022 तक कोरोना की बदलती सूरत और देश के गंभीर हुए हालात को कौन भूल सकता है। जब किसी की मौत ऑक्सीजन न मिलने की वजह से हो रही थी, तो किसी की मौत अस्पताल में बेड की व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण। मरने वालों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई थी, कि श्मशान घाटों पर कई-कई दिनों तक अंतिम संस्कार के लिए इंतजार करना पड़ रहा था। नदियों के किनारे लाशें जैसे कंकड़ के ढेर जैसी दिखाई पड़ रही थीं। मगर थोड़ा देर से ही सही स्थिति संभली और लोगों का वैक्सीनेशन हुई, तब कहीं जाकर स्थिति कंट्रोल में आ सकी थी। अब एक बार फिर कोरोना का नया वैरियंट बाहर आ गया है। हालांकि इसे पहले जितना खतरनाक तो नहीं कहा जा रहा है, मगर खुद को सुरक्षित रखने की सलाह जरूर दी जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक भारत में पिछले 7 दिनों यानी एक हफ्ते में कोरोना के 1761 मामले सामने आए हैं, जबकि 10 मौत हो चुकी हैं। जो नए वैरियंट COVID-19 New Jn-1 से संबंधित हो सकता है। हालांकि अभी सभी मामलों की पुख्ता पुष्टि नहीं की गई है। कोरोना के नए वैरिएंट JN-1 के कई मामले देश के अलग-अलग राज्यों से सामने आए हैं, केरल, गोवा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले सामने आने के बाद केंद्र और सभी राज्य सरकारों ने अलर्ट जारी किया है। डॉक्टर्स के अनुसार अगले 15 दिन बेहद अहम हैं, इस दौरान कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी देखने को मिल सकती है। डॉक्टरों ने नये वायरस से बुजुर्गों को सावधान रहने की नसीहत दी है। डॉक्टरों का कहना है कि नया वायरस पिछले वायरस से ज्यादा डेडली नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी जरूरी है। इस वैरियंट के बारे में जानने के लिए हमने दिल्ली साइंस फोरम और ऑल इंडिया पीपुल्स साइंस नेटवर्क से जुड़े डी. रघुनंदन से संपर्क किया, तो उनका कहना था कि ये समझना कि कोरोना खत्म हो चुका है, गलत होगा। हर वायरस का एक स्वभाव होता है, इसका भी है, जो धीरे-धीरे बदलता रहता है, और बदलता रहेगा। हालांकि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो पिछले जैसा खतरनाक हो। कोई घबराने वाली बात इसलिए भी नहीं है। हम इस नए वैरियंट की दशा जानने के लिए उत्तर प्रदेश चलते हैं, तो पता चलता है, पिछले 7 महीने से सब कुछ ठीक था, मगर पिछले 4 दिनों के अंदर 7 से ज्यादा केस मिल चुके हैं।

पहले गाजियाबाद में एक मामला मिला, जहां शास्त्रीनगर से भाजपा पार्षद अमित त्यागी की आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इसके बाद दो और मामले संक्रमित पाए गए। नोएडा में भी नेपाल से भारत पहुंचा एक शख्स संक्रमित पाया गया। फिर राजधानी लखनऊ में भी कोरोना का एक मरीज मिला। 75 साल की महिला कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं, उनका सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए केजीएमयू भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग महिला कुछ दिन पहले ही थाईलैंड से लौटी थीं। डब्ल्यूएचओ की पूर्व साइंटिस्ट डॉ. सौम्या स्वामीनाथन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मौसमी फ्लू जैसे इन्फ्लूएंजा ए(एचआईएन1 और एच3एन2), एडेनोवायरस, राइनोवायरस और रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस के कारण होने वाले श्वसन संक्रमण, मानसून से संबंधित बीमारियों का कारण बन सकते हैं क्योंकि इनके लक्षण भी कोविड-19 लक्षणों जैसे ही होते हैं। लक्षणों वाले हर व्यक्ति की टेस्टिंग करना संभव नहीं है इसलिए जिन्हें गंभीर लक्षण नजर आ रहे हैं, उनकी जांच करनी चाहिए। वहीं जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उन्हें गंभीर श्वसन संक्रमण या निमोनिया है, उनकी भी जांच करनी चाहिए।

ये COVID-19 New Jn-1 क्या है, इसके बारे में डब्ल्यूएचओ की ओर से यही कहा जा रहा है कि समझने के लिए अभी और अध्ययन की जरूरत है, मगर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस सब-वैरिएंट की पहली बार पहचान इसी साल अगस्त में की गई थी। यह ओमिक्रॉन का सब-वैरिएंट BA.2.86 से बना है, 2022 की शुरुआत में BA.2.86 ही कोरोना के मामलों में वृद्धि का कारण था। BA.2.86 व्यापक रूप से नहीं फैला था, लेकिन इसने विशेषज्ञों को चिंतित कर दिया था क्योंकि BA.2.86 के स्पाइक प्रोटीन पर अतिरिक्त म्यूटेशन हुए थे और उसी तरह JN-1 के स्पाइक प्रोटीन में भी एक अतिरिक्त म्यूटेशन है। वहीं विशेषज्ञों की माने तो विश्व स्तर पर मामलों में बढ़ोतरी से पता चलता है कि JN-1 एक ओमिक्रॉन का सब-वैरिएंट है जो मजबूत इम्यूनिटी वालों को भी आसानी से संक्रमित कर

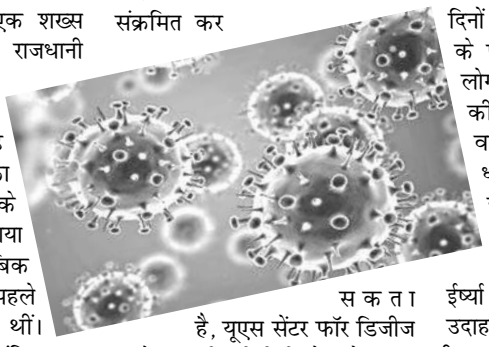

सकता है, यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी सीडीसी ने इसे यूएस में सबसे तेजी से बढ़ने वाला वैरिएंट बताया है। अगर इस वैरियंट के हो जाने की पहचान या लक्षण की बात करें तो वहीं पुरानी बीमारियां बताई जा रही हैं। जैसे बुखार, ठंड लगना, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, सांस लेने में कठिनाई, थकान, मांसपेशियों में दर्द, सिरदर्द, स्वाद या गंध की हानि, गले में खराश, नाक बहना, मतली, उल्टी और दस्त जैसी चीजें हो सकती हैं। उधर उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले देख प्रोटोकॉल जारी कर दिया गया है। सर्दी, खांसी, जुकाम और सांस के रोगियों की विशेष निगरानी की जाएगी। ऐसे मरीजों के कोरोना टेस्ट कराए जाएंगे। अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। लक्षण वाले मरीजों को टेस्ट रिपोर्ट आने तक आइसोलेशन में रखने का निर्देश दिया गया है। भीड़-भाड़ वाले इलाकों के लिए प्रोटोकॉल के पालन जरूरी होगा। भीड़ वाले स्थानों पर जाने वाले लोगों को सर्दी-जुकाम होने की स्थिति में कोरोना टेस्ट कराने के निर्देश दिए गए हैं। सभी सरकारी एवं प्राइवेट हॉस्पिटल्स और जिलों के चीफ मेडिकल ऑफिसर्स को सर्दी-खांसी वाले मरीजों पर खास निगरानी के निर्देश दिए गए है।

खैर, ये प्रशासन के प्रोटोकॉल हैं, मगर भूलना नहीं चाहिए कि अभी कुछ दिनों पहले जब प्रदेश में शीतकालीन सत्र चल रहा था, तब नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ये आरोप लगाए थे कि स्वास्थ्य के लिए बजट का 65 फिसदी अब भी खर्च नहीं किया गया है। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों की उदाहरण लें तो लखनऊ के पीजीआई में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई थी, एंबुलेंस की संख्या बढ़ाने का दावा करने वाली सरकार की राज्य में एंबुलेंस धक्का लगाकर स्टार्ट की जा ही है, जिसकी तस्वीर पिछले दिनों कानपुर से आई ही थी। फिर बची-खुची कसर राजनीतिक ईर्ष्या से पूरी हो जाती है। इसका उदाहरण आप अमेठी के संजय गांधी अस्पताल से ले सकते हैं। जिसे कई महीनों तक बंद रखने के बाद फिर चालू किया गया है। खैर, कोरोना के आंकड़ों पर लौटते हैं और आपको बताते हैं कि जबसे देश में कोविड-19 की एंट्री हुई है, डब्ल्यूएचओ के मुताबिक तब से अबतक 4 करोड़ 50 लाख, 4 हजार 816 लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। जबकि 5 लाख 33 हजार 316 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा वक्त में देश में 3420 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। जबकि अभी तक कोरोना से संक्रमित पाए गए 4 करोड़ 44 लाख 71 हजार 212 मरीज इलाज कराकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं कोरोना काल की शुरुआत से लेकर अभी तक कोरोना के कारण 5 लाख 33 हजार 332 लोगों की मौत हो चुकी है। (साभार)

कानूनी सलाह

शिवानंद गिरि

(अधिवक्ता)

Ph.- 9308454485
7004408851

E-mail :-
shivanandgiri5@gmail.com

✯ फरलो क्या होता है?

जो भी जेल के अंदर होता है, उन्हें एक साल के अंदर 70 दिन की पैरोल दी जाती है। इसी के साथ कैदी को 21 से 28 दिन की फरलो मिलना उनका अधिकार है। आम आदमी के कार्यकाल में फरलो का मतलब अनुपस्थिति की छुट्टी देना है। हालाँकि कानूनी शब्दों में यह जेल से एक दोषी को एक निर्दिष्ट समय अवधि के लिए अनुपस्थिति की छुट्टी देने को संदर्भित करता है। प्रत्येक राज्य के जेल नियमों में फरलो देने के नियम और प्रक्रिया निर्धारित की गई है। हालाँकि फरलो की व्यापक अवधारणा सभी राज्यों में समान रहती है और केवल इसे करने की प्रक्रिया अलग-अलग राज्यों में भिन्न होती है।

✯ कैदी के लिए फरलो क्या है?

फरोल आमतौर पर उस कैदी को दी जाती है जिसे काफी लंबे वक्त के लिए सजा मिली हो. फरलो को कैदी की सजा में छूट और उसके अधिकार के तौर पर देखा जाता है. एक कैदी को फरलो देने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन परोल के लिए कारण होना काफी जरूरी है।

✯ पैरोल क्या है?

पैरोल आपराधिक न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ होता है किसी सजायाफ्ता कैदी को सजा पूरी होने से पहले कुछ वक्त के लिए या पूरी तरह रिहा कर दिया जाना। हालांकि पैरोल देते वक्त कैदी के अच्छे व्यवहार को ध्यान में रखा जाता है। साल 1894 के जेल अधिनियम और 1900 के कैदी अधिनियम के तहत पैरोल की प्रक्रिया निर्देशित होती है। इसी के मुताबिक हर राज्य में पैरोल दिशा-निर्देशों का अपना सेट होता है, जो एक-दूसरे से थोड़ा भिन्न होता है। पैरोल सुधार की प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसका मकसद कैदियों को समाज से फिर से जोड़ना होता है। ये दो प्रकार का होता है- कस्टडी पैरोल और रेगुलर पैरोल । कस्टडी पैरोल के अंतर्गत दोषी अथवा अपराधी को किसी विशेष स्थिति में जेल से बाहर लाया जाता है, और उस समय वह पुलिस कस्टडी में ही रहता है। पुलिस का सुरक्षा घेरा उसके साथ होता है, जिससे कि वह फरार ना हो सके। इस प्रकार की पैरोल अपराधी को तब दी जाती है, जब उसके परिवार में किसी खास रिश्तेदार की मौत हो जाती है, या फिर उसके परिवार में किसी विशेष व्यक्ति की शादी होती है। उसके परिवार में यदि कोई बीमार होता है, या फिर कोई भी ऐसी परिस्थिति जो कि अपराधी के लिए बहुत आवश्यक है, तो उस अपराधी को पैरोल पर कुछ घंटों के लिए बाहर लाया जाता है।

रेगुलर पैरोल की स्थिति में वह अपराधी जिसे सजा सुनाई जा चुकी होती है, तो वह रेगुलर पैरोल के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए आवश्यक है, कि वह अपराधी कम से कम एक साल की सजा जेल में काट चुका हो, और जेल में उस अपराधी का व्यवहार अच्छा हो। इसके अलावा यदि वह पहले भी जमानत पर रिहा हो चुका है तो उसका ऐसा रिकॉर्ड होना चाहिए कि उस जमानत के दौरान अपराधी ने कोई अन्य अपराध ना किया हो। रेगुलर पैरोल एक साल में कम से कम एक महीने के लिए दी जा सकती है। रेगुलर पैरोल भी कुछ खास परिस्थितियों में ही दी जा सकती है। उदाहरण के तौर पर सजायाफ्ता के परिवार में कोई बीमार हो, किसी विशेष व्यक्ति का परिवार में विवाह हो या फिर किसी परिस्थिति में मकान की मरम्मत करानी बहुत जरुरी हो, यदि परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गयी हो, यदि पत्नी गर्भवती हो और डिलीवरी होनी हो और घर में कोई और व्यक्ति देख रेख के लिए ना हो और इसके अलावा किसी और प्रकार का ऐसा काम हो जिसे पूरा किया जाना अपराधी के लिए जरुरी हो जैसे कि अपना वसीयत तय करना। इसके अलावा भी रेगुलर पैरोल मिलने के लिए कई कानूनी नियम एवं शर्तें होती हैं। उदाहरण के लिए राम रहीम को रेगुलर पैरोल पर ही छोड़ा गया था। कुछ ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं जब पैरोल के आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है उदाहरण के तौर पर :-

1. अगर अपराधी का व्यवहार जेल में संतोषजनक ना हो
2. यदि अपराधी पहले कभी पैरोल पर बाहर आया हो और उसने पैरोल की शर्तों का का उल्लंघन किया हो
3. बेहद ही गंभीर अपराध किया हो जैसे कि बलात्कार के बाद हत्या, देशद्रोह और आतंकवादी गतिविधि में शामिल होना आदि

पैरोल के जैसा ही एक फरलॉ होता है इसमें भी कैदियों को कुछ समय के लिए रिहा किया जाता है। लेकिन पैरोल और फरलों में कुछ मूलभूत अंतर होता है जैसे कि पैरोल किसी भी कैदी का अधिकार नहीं होता जबकि फरलॉ कैदी का अधिकार माना जाता है। पैरोल मिलने की कुछ उचित वजह होती हैं और रिहाई के बाद दोषी को तय वक्त में अधिकारियों के आगे हाजिरी लगानी होती है। वहीं फरलॉ लंबे वक्त के लिए सजा काट रहे कैदियों को एक तय समय में दी जाने वाली छुट्टी होती है। इसका मकसद लंबे वक्त तक सजा काटने से पड़ने वाले बुरे असर को दूर करना और सामाजिक रिश्ते बनाए रखना होता है। फरलॉ को सजा में माफी के तौर पर भी देखा जाता है।

GSTIN : 10KEPD0123PIZP

उत्तर भारत का COOKIE MAKER, सीवान में पहली बार
आपके लिए लेकर आया है
Cookie का बेहतर श्रृंखला

PRATIK ENTERPRISES

राजपुर (रघुनाथपुर) में अत्याधुनिक मशीनों द्वारा रस्क, बिस्कुट, बर्गर, मीठा ब्रेड, वंद, क्रीम रोल, पेटीज और बर्ड डे केक, पार्टी केक ग्राहकों के मनपसंद तैयार किया जाता है।

शुद्धता एवं स्वाद की 100% गारंटी

किसी भी अवसर पर
एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।

प्रतीक फुड कंपनी

प्रतीक इंटरप्राइजेज, प्रतीक पतंजलि
राजपुर, रघुनाथपुर, सीवान (बिहार)

-: सौजन्य से :-

ब्रजेश कुमार दुबे

Mob.-9065583882, 9801380138

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.
(Serving nation since 1990)

WESTOCITRON
WESTOCLAV
WESTOFERON
WESTOPLEX
QNEMIC

AOJ
AZIWEST
DAULER
MUCULENT
AOJ-D
BESTARYL-M
GAS-40
MUCULENT-D

SEVIPROT
WESTOMOL
WESTO ENZYME
ZEBRIL

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.
Industrial area, Fatuha-803201
E-mail- westerlindrugsprivatelimited@gmail.com
Phone No.:0162-3500233/2950008